सांध्य दैनिक
# नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

**सु-विचार**

*" अपनत्व का कोई रुप नहीं होता,*
*जब किसी की अनुभूति स्वयं से भी अच्छी लगे,*
*वहीं अपनत्व है...! "*

*अज्ञात...*

वर्ष–01 अंक–93 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, गुरुवार 23 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

## ऑपरेशन अंकुश का असर : सट्टा सिंडिकेट पर पुलिस की कड़ी चोट, बड़े खाईवालों ने किया सरेंडर

*नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़*

जिले में अवैध जुआ-सट्टा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन अंकुश का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। पुलिस की लगातार दबिश, सख्त कार्रवाई और रणनीतिक घेराबंदी से सटोरियों में खौफ का माहौल है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कुख्यात सट्टा खाईवाल अब खुद सामने आकर सरेंडर करने लगे हैं।

इसी कड़ी में लंबे समय से सक्रिय खाईवाल हेमराज बरेठ उर्फ पप्पू बरेठ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं एक अन्य बड़े सटोरिये मोहम्मद शाहनवाज मलिक उर्फ शानू ने कोतवाली थाना पहुंचकर सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस की कार्रवाई केवल सट्टा लिखने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सीधे खाईवालों और पूरे नेटवर्क के सरगनाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। यही वजह है कि वर्षों से सक्रिय सट्टा सिंडिकेट की कमर टूटती नजर आ रही है। लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी के डर से फरार आरोपी खुद कानून के दायरे में आने को मजबूर हो रहे हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हेमराज बरेठ के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। वर्ष 2023 में थाना चक्रधरनगर में दो प्रकरण, 2024 और 2025 में जूटमिल थाना में मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2026 में भी उसका नाम सट्टा प्रकरणों में सामने आया था। बताया जा रहा है कि उसका पारिवारिक संबंध भी सट्टा कारोबार से रहा है। वहीं मोहम्मद शाहनवाज मलिक के खिलाफ वर्ष 2026 में ही कोतवाली थाना में चार अलग-अलग प्रकरण दर्ज हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि वह कमीशन के आधार पर सट्टा संचालन से जुड़ा हुआ था, जबकि उसका सहयोगी एजाज खान अभी भी फरार है।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में अवैध जुआ-सट्टा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई केवल दमनात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक भी है—जो लोग अपराध छोड़कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं, उन्हें अवसर दिया जाएगा, लेकिन जो नहीं सुधरेंगे उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई तय है। पुलिस की इस सख्ती से साफ संकेत मिल रहे हैं कि रायगढ़ में अब सट्टा नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे व कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

## स्टेट बार काउंसिल में अनुशासन व नियम निर्माण समिति के चेयरमैन बने प्रशांत तिवारी

### अधिवक्ताओं में हर्ष बधाईयों का लगा तांता

*नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव*

छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल सदस्यों के निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात स्टेट बार काउंसिल के विभिन्न समितियों का गठन विगत दिनों उच्च न्यायालय बिलासपुर परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें राजनांदगांव के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद में लगातार निर्वाचित होने वाले अधिवक्ता प्रशांत प्रभात तिवारी राज्य अधिवक्ता परिषद के अनुशासन समिति एवं नियम निर्माण समिति के चेयरमैन के रूप में चुने गए हैं।

न्याय मार्ग में अनुशासन एवं नियम का बहुत अधिक महत्व होता है और इन दोनों महत्वपूर्ण समितियों में श्री तिवारी की चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है उच्च न्यायालय बिलासपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में ख्याति प्राप्त अधिवक्ता स्व. प्रभात तिवारी के ज्येष्ठ सुपुत्र प्रशांत तिवारी अपने सिद्धांतों और स्पष्टवादीता के लिए खासे चर्चित हैं।

हाल में संपन्न चुनाव में वे स्पष्ट बहुमत के साथ निर्वाचित होकर अनुशासन एवं नियम निर्माण समिति के चेयरमैन नियुक्त होने के साथ-साथ छ ग राज्य अधिवक्ता परिषद में भवन निर्माण समिति एवं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए गठित अधिवक्ता कल्याण समिति के भी सदस्य नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्ति से जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, चौकी सहित प्रदेश के अधिवक्तागण, इष्ट मित्र, शुभचिंतकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है।

### श्री भवाल माताजी मंदिर का प्रतिष्ठा व ध्वजारोहण कल से

**राजनांदगांव।** खैरागढ़ के अमलीपारा में स्थापित एवं प्रतिष्ठित श्री भवाल माताजी मंदिर का प्रतिष्ठा वर्षगांठ एवं ध्वजारोहण उत्सव 24 अप्रैल से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सकल श्रीसंघ, एवं श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। आयोजन के तहत पहले दिन 24 अप्रैल को प्रात: 8 बजे से हवन यज्ञ पूजा विधान का मांगलिक कार्यक्रम एवं शाम 7.30 बजे से भक्ति भावना संगीतकार अंकित लोढ़ा, पंडरिया- रायपुर द्वारा भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं दूसरे दिन 25 अप्रैल को सुबह 6 बजे से माता का विशेष अभिषेक किया जाएगा। सुबह 8 बजे से वरघोड़ा जुलूस निकलेगा। इसके बाद सुबह 9.15 बजे शुभ मुहूर्त पर ध्वजारोहण और कार्यालय भवन का लोकार्पण किया जाएगा। शाम 7.30 बजे भक्ति भावना में गोपाल सिसोदिया द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। बता दें कि जुलूस में पधारने वाले श्रद्धालुओं के लिए नवकारसी की व्यवस्था रहेगी।

## दुर्ग पुलिस पर आईजी की सख्ती : एसपी कार्यालय और मोहननगर थाना का निरीक्षण

### लंबित मामलों पर जताई नाराजगी, अभिलेखों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की

*नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग*

जिले की पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग और थाना मोहननगर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने लंबित मामलों, अभिलेखों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए।

आईजी ने स्पष्ट कहा कि लंबित प्रकरणों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक मामले का शीघ्र निराकरण करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में आईजी ने सभी सेक्शन प्रमुखों के साथ चर्चा कर समन्वय बेहतर करने और जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनुशासन और टीमवर्क जरूरी है।

इसके बाद थाना मोहननगर का निरीक्षण करते हुए आईजी ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, विवेचना की गुणवत्ता और जनसुनवाई प्रणाली का जायजा लिया। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और संवेदनशील तरीके से समाधान किया जाए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चन्द्रा, डीएसपी तनुप्रिया, डीएसपी सीपी तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आईजी के इस निरीक्षण को पुलिस विभाग में कार्यप्रणाली सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

## नंदिनी खुंदिनी ग्राम पंचायत में घटिया नाली निर्माण कार्य

### उखड़ी सड़क से जनता हुई बेहाल

*नई दृष्टिबिंदु / नंदिनी अहिवारा*

ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी में विकास कार्यों की पोल उस समय खुल गई जब हाल ही में बनाई गई नाली और सड़क की हालत बदतर नजर आने लगी। लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद नाली निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

#### ग्रामीणों की मुख्य समस्याएं

गांव में बनाई गई नाली जगह-जगह से टूटी और अधूरी पड़ी है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर गंदा पानी जमा हो रहा है। सड़क पूरी तरह ऊबड़-खाबड़ हो चुकी है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल। बरसात के मौसम में स्थिति और भयावह होने की आशंका है।

#### ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है। घटिया सामग्री का उपयोग कर सिर्फ खानापूर्ति की गई, जबकि कागजों में पूरा काम दिखाकर राशि निकाल ली गई। लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार हुआ है।

#### जनता में आक्रोश

स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोजाना इसी खराब सड़क और गंदगी से गुजरना उनकी मजबूरी बन गया है।

#### प्रशासन से मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नाली और सड़क का पुनः गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। जहां एक ओर सरकार ग्रामीण विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं नंदिनी खुंदिनी जैसे गांवों में जमीनी हकीकत इन दावों की सच्चाई बयां कर रही है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो जनता का आक्रोश और बढ़ सकता है।

## टैक्स के 'विस्फोट' को रोकने को महापौर मधुसूदन यादव का यू-टर्न, निगम के अदूरदर्शी फैसलों पर उठे गंभीर सवाल

*नरेन्द्र डाकलिया / राजनांदगांव*

नगर निगम राजनांदगांव में पिछले कुछ दिनों से जारी टैक्स विवाद के बीच महापौर ने एक बड़ा 'यू-टर्न' लिया है। जिस टैक्स वृद्धि को लेकर शहर भर में आक्रोश था, उसे बैकफुट पर आते हुए महापौर ने कम कर दिया है। लेकिन, यह फैसला राहत से ज्यादा निगम के उन प्रशासनिक अधिकारियों और सलाहकारों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़ा कर गया है, जिन्होंने जनता की जेब पर डाका डालने वाली इस 'अवैज्ञानिक' टैक्स नीति को तैयार किया था।

#### क्या थी अधिकारियों की मंशा?

यह सवाल हर नागरिक के मन में है: जिस तरह से सम्पत्तिकर में भारी और अप्रत्याशित वृद्धि की गई थी, उससे शहर में हाहकार मचने की स्थिति पैदा हो गई थी। निगम के जिन अधिकारियों और परामर्शदाताओं ने टैक्स की दरों में यह 'बेहिसाब' बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया, क्या वे वास्तव में शासन की छवि खराब करना चाहते थे? जानकार इसे महज एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि आगामी चुनावों को देखते हुए राजनैतिक छवि को नुकसान पहुँचाने की एक 'साजिश' के रूप में देख रहे हैं।

**कुछ प्रमुख प्रश्न जो निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं:**

**सलाहकारों की योग्यता:** ऐसे कौन से परामर्शदाता हैं जो जमीनी हकीकत जाने बिना जनता पर आर्थिक बोझ डालने का सुझाव देते हैं?

**जनविरोधी रवैया:** बिना सोचे-समझे थोपे गए इस कर ने निगम की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में ला दिया है।

**राजनैतिक दुष्प्रचार:** क्या निगम के अंदर बैठे कुछ तत्व जानबूझकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में जनाधार खिसकाने का प्रयास कर रहे थे?

#### परिवर्तित दरों का गणित (राहत का दावा, पर सवाल बरकरार)

महापौर परिषद की बैठक में हुई नई घोषणा के अनुसार, अब संपत्ति कर में दरों को संशोधित किया गया है: खुली भूमि एवं आवासीय संपत्ति: अब 10 प्रतिशत की वृद्धि। व्यवसायिक/औद्योगिक संपत्ति: अब 20 प्रतिशत की वृद्धि। निगम का दावा है कि यदि पुरानी दर से 2,000 रुपये टैक्स लग रहा था, तो नई बढ़ी दरों के अनुसार यह लगभग

2,200 रुपये होगा (जो पहले 4,000-5,000 तक पहुंच रहा था)। निगम इसे 'राहत' बता रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब पूर्व में वृद्धि नहीं हुई थी, तो अचानक इस कदर 'लूट' की योजना क्यों बनाई गई?

#### जवाबदेही तय हो

शहर के निवासियों का कहना है कि यह निर्णय जनता के व्यापक विरोध और दबाव का नतीजा है। यदि जनता ने समय रहते आवाज नहीं उठाई होती, तो आज शहर की आर्थिक कमर टूट चुकी होती। अब समय आ गया है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए जिन्होंने इस अव्यावहारिक टैक्स नीति को तैयार किया था। क्या महापौर इन अधिकारियों और सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या फिर यह 'टैक्स का खेल' आगे भी किसी और रूप में जारी रहेगा?

### महापौर परिषद की बैठक में दुगनी बढ़ी दर में कटौती कर खुली भूमि व आवासीय भूमि के लिए 10 प्रतिशत व व्यवसायिक/औद्योगिक के लिए 20 प्रतिशत हुआ निर्धारण

कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार सम्पति करो की दरो में संशोधन प्रति वर्ष किया जाना है। किन्तु पिछले 09 वर्षो में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड तथा प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार ए.आर.ही. (वार्षिक भाडा मूल्य) दर का निर्धारण किया गया था, जिसे नियमानुसार सामान्य सभा से उक्त दरो की स्वीकृति पश्चात अप्रैल माह से 2026-27 के सम्पत्तिकर लिया जा रहा है।

प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार दरो में संशोधन से सम्पतिकर की दरों में वृद्धि हुई साथ ही पूर्व वर्षों में सम्पति कर की गणना प्रक्रिया तथा शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सम्पतिकर की गणना प्रक्रिया के कारण वर्तमान वर्ष के सम्पतिकर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। चुकि वर्षो से सम्पतिकर में वृद्धि नही की गयी थी और इस वर्ष नियमो के तहत तथा कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार दर निर्धारित करने पर सम्पतिकर में लगभग सभी वाडी में अप्रत्यासित वृद्धि हुई। जिससे जनसामान्य पर सम्पतिकर वृद्धि का आर्थिक बोझ पड़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में सम्पतिकर दुगुना तथा कही कही दुगुना से ज्यादा वृद्धि हो गयी। जिसका जनसामान्य पर आर्थिक बोझ बढ़ गया।

महापौर मधुसूदन यादव से बढ़ी दर के आधार पर इस वर्ष जिन लोगो के सम्पतिकर में डबल से ज्यादा वृद्धि हुई उन लोगो जानकारी दी। संज्ञान में उक्त विषय आने पर महापौर श्री यादव ने महापौर परिषद की बैठक आहुत कर जनसामान्य को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्त करने एवं निकाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने को ध्यान में रखते हुऐ, पुर्नविचार कर सम्पतिकर के दर में संशोधन किया।

पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 के दरो में निम्नानुसार संशोधन कर वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु लिये जाने वाले सम्पतिकर का सुधार करने का निर्देशित किया है। जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में खुली भूमि एवं आवासीय सम्पति पर दर 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार पर व्यवसायिक/औद्योगिक सम्पति पर सम्पतिकर 20 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया। अर्थात यदि किसी आवासीय सम्पति पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पतिकर 2 हजार रूपये लग रहा है जो नई बढ़ी दर से कई क्षेत्रों में 4 हजार से 5 हजार हो रहा था उसे कम कर 10 प्रतिशत के आधार पर इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पतिकर 2 हजार में 2 सौ रूपये वृद्धि कर 2 हजार 2 सौ रूपये लिया जावेगा। इस प्रकार 3 हजार रूपये कम करने का प्रयास किया गया।

इसी प्रकार खुली भूमि में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पतिकर 1 हजार रूपये लग रहा है तो उसे इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पतिकर 1 हजार 1 सौ रूपये लगेगा एवं व्यवसायिक/औधोगिक सम्पति वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पतिकर 30 हजार रूपये लग रहा है तो उसे इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पतिकर 30 हजार 6 सौ रूपये लगेगा। इस प्रकार महापौर ने पुनर्विचार कर इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के सम्पतिकर में 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत दर में वृद्धि कर भार को कम करने का प्रयास किया है।

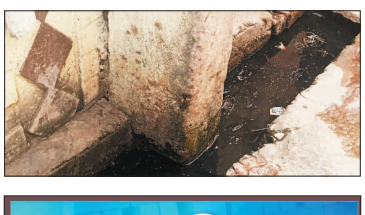

# महतारी वंदन ई-केवाईसी व्यवस्था, जल संकट, प्रवेश प्रक्रिया व नसबंदी प्रकरण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

## कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, दुर्ग कांग्रेस अध्यक्ष धीरज ने कहा- आमजन की समस्यों के निदान के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर

*नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग*

जिला कांग्रेस कमेटी, दुर्ग शहर के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने आज जिला कलेक्टर को शहर की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आम नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई।

ज्ञापन में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी केंद्रों में महिलाओं को हो रही परेशानियों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया। भीषण गर्मी में बड़ी संख्या में महिलाएं लंबी कतारों में खड़ी रहने को मजबूर हैं, वहीं कई केंद्रों पर छाया, पेयजल एवं बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साथ ही कुछ स्थानों पर अनियमित शुल्क लिए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिस पर रोक लगाने एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके साथ ही शहर में गहराते

जल संकट का मुद्दा उठाते हुए बताया गया कि पानी की अनियमित आपूर्ति एवं लो प्रेशर के कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से जल आपूर्ति को नियमित करने एवं प्रभावी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने की मांग की गई। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी अव्यवस्थाओं की शिकायत करते हुए इसे सरल, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने की मांग रखी गई, ताकि अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसके अतिरिक्त नसबंदी ऑपरेशन के दौरान हुई महिलाओं की मृत्यु के मामले को गंभीरता से उठाते हुए कहा गया कि अब तक न तो मृत्यु के कारण स्पष्ट किए गए हैं, न जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और न ही पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इस मामले में शीघ्र जांच पूरी कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने एवं मुआवजा देने की मांग की गई। इस संबंध में धीरज बाकलीवाल ने कहा कि, शहर में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार लापरवाही सामने आ रही है, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को इन विषयों पर गंभीरता से संज्ञान लेकर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। यदि समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी जनहित में आगे की रणनीति बनाने के लिए बाध्य होगी।

ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से आग्रह किया गया कि सभी समस्याओं पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, दीपक साहू, प्रेमलता साहू, कन्या धीमर, आनंद ताम्रकार, गुरदीप सिंह भाटिया, देवश्री साहू, ओमप्रकाश जोशी, ज्ञानदास बंजारे, मुकेश साहू, सुरेंद्र राजपूत, राहुल शर्मा, देव सिन्हा, अनूप वर्मा, गौरव उमरे, निकिता मिलिंद, लोकेश सोनी, भीम सेन, नंदा रावत, आयुष शर्मा, अमित मिश्रा, अली असगर सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

**खास खबर**

## कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र कौशिक के बयान पर भाजपा का पलटवार, माफी की मांग

*नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग*

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उसे आपत्तिजनक और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग देश की गरिमा और सवीच्च पद का अपमान है।

सुरेंद्र कौशिक ने अपने जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नियंत्रण जैसे कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, तुष्टीकरण और घमंड की राजनीति से ग्रस्त है। कौशिक ने कहा कि जब कांग्रेस विकास और जनहित के मुद्दों पर जवाब देने में असफल होती है, तब इस तरह की भाषा का सहारा लेती है, जो उसकी हताशा को दर्शाता है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी न केवल प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि देश की जनता के जनादेश का भी अनादर है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी को भी मर्यादित भाषा का उपयोग करने की नसीहत दी। सुरेंद्र कौशिक ने मांग की कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा और संवैधानिक पदों का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है।

### उप निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय शिकायत सेल का गठन

**दुर्ग।** नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण का कार्य जिले में प्रभावशील है। नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन होना प्रस्तावित है। आगामी निर्वाचन से संबंधित शिकायत पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिला स्तरीय शिकायत सेल का गठन किया गया है। यह शिकायत सेल भू-अभिलेख कक्ष क्रमांक 21 में संचालित होगा। इसके संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों और कमर्चारियों की ड्यूटी उनके पूर्व दायित्वों के साथ अतिरिक्त रूप से लगाई गई है। शिकायत सेल में अधीक्षक भू-अभिलेख सुश्री रेखा राजपूत मोबाइल नंबर 8359809792 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ सहायक प्रभारी अजय मेरावी (सहायक अधीक्षक) 7987028422 जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा श्रीमती उज्जवला ध्रुव (सहायक ग्रेड-02), सुश्री साधना वर्मा (कम्प्यूटर ऑपरेटर) तथा राहुल यादव (भृत्य) की ड्यूटी लगाई गई है, जो विभिन्न सहायक कार्यों का निर्वहन करेंगे।

# स्वास्थ्य विभाग का निर्देश : टीकाकरण व दूसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम समयसीमा में पूरा करें

## बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा, निजी अस्पताल में प्रसव पर जताई नाराजगी

*नई दृष्टिबिंदु / भिलाई*

दुर्ग जिला के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने चरोदा भिलाई-3 के स्वास्थ्य अमले की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की गहन समीक्षा की। इस दौरान वर्ष 2026-27 मे लक्ष्यों के अनुरूप गुणवत्ता ओर मानक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं जन मानस तक उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए।

इस दौरान मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम,शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिजिल्स रूबैला उन्मूलन अभियान, भारत मुक्त टी बी अभियान 2.0 , राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम संस्था गत प्रसव ओर शिशु दर कम करने और माता मृत्यु दर में कमी लाने पर चर्चा की गई। इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी गई कि चरोदा भिलाई 3 अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका व स्वास्थ्य संयोजक एवं एएनएम और एम पी डब्लू डाटा हेल्डर जे एस ए के साथ उनके संस्थानों में प्राप्त लक्ष्य अनुसार किया गया।

बी ई टी ओ सैय्यद असलम ने बतलाया कि दिसंबर 2026 तक मिजिल्स रूबैला उन्मूलन अभियान के लिए 10 वर्ष तक की आयु में छूटे हुए हितग्राहियों को खसरा टीका लगाया जाएगा।इसके लिए प्रथम 9 माह का खसरा टीका और डेढ़ वर्ष का एम आर सेकंड डोज शत प्रतिशत को लगाया जाएगा। जहां तीन वर्षो के अंदर मिजिल्स आउट ब्रेक हुआ हो ऐसे हाई रिस्क एरिया और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां खसरा का टीकाकरण से लोग वंचित हो गए हो, वहां विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव गलेड ने आधार बेस्ड उपस्थिति इन-आउट दोनों समय लगाने, वयवंदन कार्ड बनाने और सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपसी समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों को प्राप्त करने निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम प्रबंधक डा भूमिका वर्मा ने ए्न सी डी अंतर्गत नवीन समूहों को स्क्रीनिंग करने, पुराने केसेस का फॉलोअप करने और बाल मधुमेह रोगियों की सूची तैयार कर विभाग की योजनाएं समझने निर्देश दिए। वहीं उन्होंने शासकीय अस्पतालों में छोड़कर निजी अस्पताल मे प्रसव कराए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रति माह 3 और चरोदा भिलाई-3 में प्रति माह 10 समान्य प्रसव कराने निर्देश दिए। इस दौरान जानकारी दी गई कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 समान्य प्रसव मामले में लक्ष्य से दोगुना हासिल करने में सफल रहा है।

क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉ अभिषेक श्रीवास्तव ने भारत मुक्त टी बी अभियान 2.0 के संबंध में लक्षित समूह मे 60 वर्ष से उपर तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों ओर टी बी के लक्षण वाले लोगों को खखार जांच और एक्स-रे जांच कराने माइक्रो प्लान बनाकर लक्ष्य प्राप्त करने निर्देश दिए। डॉ. रश्मि भोसले ने एच पी व्ही वैक्सीन लगाने के जन जागरूकता अभियान चलाने और उन बालिकाओं को जिनका 14 वर्ष पूर्ण हो चुका है लेकिन 15 वां जन्मदिन नहीं मनाई है, उन्हें समीप के स्वास्थ्य केन्द्रों में सिंगल डोज एच पी व्ही वैक्सीन लगाने भेजने निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में विभिन्न टीको को शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने और छूटे हुए शिशुओं को विशेष टीकाकरण अभियान में अनिवार्य रूप से टीकाकरण करने निर्देश दिए।

मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम में डॉ. भूमिका वर्मा और समन्वयक शोभिका गजपाल ने हाई सिस्क गर्भवती महिलाओं को एच आर पी पोटेल मे दर्ज कर ट्रैकिंग कर सुरक्षित प्रसव कराने निर्देश दिए। जिला डाटा प्रबंधक राखी सोनी ने कार्य करने के बाद ऑन लाइन एंट्री और रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी दी। वहीं क्षेत्र से पंजीकरण से छूट रही गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के अंतर ढूंढने और शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के तरीके समझाते हुए डाटा अंतर मे प्रकाश डाला।

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ भुवनेश्वर कुमार कठौतिया ने कहा कि इस प्रारंभिक सत्र वर्ष 2026-27 मे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में योजनाबद्ध तरीके से काम करने निर्देश दिए। बैठक में डॉ. शिखर अग्रवाल मेडिकल ऑफिसर भिलाई-3, डॉ. कीर्ति तिर्की शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरोदा,सीटी प्रोग्राम मैनेजर डॉ. विवेक मिंज, बी ई टी ओ सैय्यद असलम, एल एच व्ही आर विश्वास, टीबी समन्वयक इंदु अमृत ,टी बी प्रयोगशाला तकनीशियन मोहम्मद फारूख और टी बी एचबी राहुल यादव सहित स्वास्थ्य अमले के लोग उपस्थित थे।

## दुर्ग में वाहन चेकिंग के दौरान 2 किलो से अधिक गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार

*नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग*

थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नयापारा चौक में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा की अवैध बिक्री के लिए ले जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2.176 किलोग्राम गांजा सहित मोबाइल फोन और धारदार हथियार जप्त किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार 22 अप्रैल 2026 को नयापारा चौक में नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से प्लास्टिक की झिल्ली में रखे तीन पैकेट में गांजा बरामद हुआ।

पूछताछ में आरोपी ने गांजा को बिक्री के लिए ले जाना स्वीकार किया। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में जप्ती की कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख), 27(क) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध क्रमांक 207/2026 दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उमेश यादव उर्फ दादू (20 वर्ष), निवासी शिवपारा सात डेमली पेड़ के पास, दुर्ग के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1,08,800 रुपये कीमत का 2.176 किलोग्राम गांजा, एक पुराना मोबाइल फोन (कीमत लगभग 1,000 रुपये) और एक धारदार हथियार (कीमत लगभग 500 रुपये) जप्त किया है। कुल जप्त सामग्री की कीमत 1,10,300 रुपये आंकी गई है।

इस कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली के निरीक्षक नवीन कुमार राजपूत, प्रधान आरक्षक राकेश निर्मलकर, आरक्षक केशव कुमार, गजेन्द्र यादव तथा एसीसीयू टीम के सहायक उप निरीक्षक किरेन्द्र सिंह और आरक्षक अलाउद्दीन शेख की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग मिल सके।

## केमिकल फैक्ट्रियों पर विधानसभा में उठे सवाल, गोलमोल जवाब के बाद विधायक देवेन्द्र ने ईओडब्ल्यू को लिखा पत्र

*नई दृष्टिबिंदु / भिलाई*

दुर्ग जिले में एक ही पते पर अलग-अलग केमिकल फैक्ट्रियों के संचालन का मुद्दा अब और गरमा गया है। यह मामला भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने ही विधानसभा में उठाया था, जहां पूछे गए प्रश्न के जवाब में सामने आई जानकारी कई स्तर पर सवाल खड़े करती है। जवाब से असंतुष्ट विधायक ने अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण में हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।

विधानसभा में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वहीं, उसी जवाब में यह भी उल्लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 24 फरवरी 2025 को चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर जिले के 16 कोलतार प्रोसेसिंग आधारित उद्योगों की जांच कराई। जांच में 8 उद्योग पर्यावरणीय सहमति शर्तों के उल्लंघन के दोषी पाए गए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा 24 जून 2025 को प्राप्त एक शिकायत में उद्योगों द्वारा तथ्यों को छिपाकर केंद्रीय पर्यावरण स्वीकृति लेने का आरोप लगाया गया, लेकिन इस पर जांच समिति का गठन नहीं किया गया। एक अन्य शिकायत पर पर्यावरण मंडल ने पत्र क्रमांक 8879 7 जुलाई 2025 के माध्यम से उद्योग संचालनालय सहित अन्य विभागों को पत्राचार किया। मामला ईओडब्ल्यू तक भी पहुंचा, जहां शिकायत क्रमांक 02/2025 पंजीबद्ध है और प्रतिवेदन लंबित है।

विधायक देवेंद्र यादव ने 20 अप्रैल को ईओडब्ल्यू को लिखे पत्र में कहा है कि विधानसभा में दिए गए जवाब में विरोधाभास है—एक ओर शिकायत नहीं होने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर जांच और उल्लंघन की पुष्टि भी की गई। उन्होंने अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी है। पूरे मामले में शिकायत न होने के दावे, जांच का गठन, उल्लंघन की पुष्टि और कार्रवाई की स्पष्ट स्थिति सामने न आने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

## महापौरने महिला समृद्धि बाजार का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश

*नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग*

नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत गौरवपथ स्थित महिला समृद्धि बाजार का महापौर अलका बाघमार द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभारी शेखर चन्द्राकर एवं निगम बाजार विभाग अमला के समृद्धि बाजार परिसर का जायजा लिया तथा उपस्थित व्यापारियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

महापौर ने निरीक्षण के दौरान बाजार परिसर में व्याप्त स्वच्छता संबंधी खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाजार में आने वाले ग्राहकों, विशेषकर महिलाओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

निरीक्षण के दौरान महापौर विभिन्न दुकानों में पहुंचीं और वहां की व्यवस्थाओं

का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि परिसर में कितनी दुकानों का आवंटन हुआ है तथा कितनी दुकानें किराए पर संचालित हो रही हैं। इस पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमों के विरुद्ध संचालित सभी दुकानों पर तत्काल कारवाई की जाए तथा संबंधित दुकान संचालकों को उसी दिन नोटिस जारी किया जाए।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार की स्थापना की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को व्यवसायिक अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस उद्देश्य की पूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने यह भी कहा कि बाजार की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं, ताकि यह बाजार शहर की महिलाओं के लिए एक आदर्श व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

# पतंजलि के बाल योग गुरुकुल ग्रीष्मकालीन शिविर में निखारेंगे बच्चों का व्यक्तित्व

## योग, संस्कार और जीवन कौशल का होगा अनूठा संगम, 3 मई से कोहका में होगा महीने भर का आयोजन

*नई दृष्टिबिंदु / भिलाई*

पतंजलि योग समिति, जिला दुर्ग की ओर से बाल योग गुरुकुल ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 का आयोजन 3 मई से 27 मई तक पतंजलि गौशाला परिसर, कोहका, भिलाई में किया जा रहा है। ग्रीष्म अवकाश को बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सार्थक बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में कक्षा छठवीं से 12वीं तक के बालक-बालिकाओं को योग, भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा एवं जीवन कौशल का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक इस शिविर में बच्चों के लिए योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एवं ध्यान, गीता एवं रामायण के श्लोक, चौपाइयों का अध्ययन और जीवन में प्रयोग,जीवन कौशल ( अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता), संस्कार आधारित खेल एवं योग प्रतियोगिताएं, चित्रकला, भजन, नाटक, वकृत्व एवं रचनात्मक

गतिविधियाँ, सेवा कार्य, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां होंगी। इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह विशेष थीम के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, संस्कार, आत्मविश्वास एवं आध्यात्मिकता का विकास किया जाएगा। जिले के सभी जोनों का सक्रिय सहयोग रहेगा।

इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने हेतु पतंजलि योग समिति, जिला दुर्ग के चारों जोनों के पदाधिकारी एवं योग शिक्षक सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इनमें दुर्ग जोन से उद्धव राम साहू, संदीप गुप्ता, सेक्टर जोन से जयंत भारती, राजेश तिवारी, बिसेन, वैशाली नगर जोन से शंभू कुशवाहा, तिजऊ राम साहू, अनूप बंसल, एस.के. रंधावा, भिलाई-3 जोन से श्रीनिवास राव, आर.के. वैद्य एवं अन्य समर्पित पतंजलि कार्यकर्ता शामिल हैं। इस शिविर में प्रवेश हेतु अभिभावक अपने बच्चों का पंजीयन ऑनलाइन लिंक के माध्यम से होगा। वहीं सीधे पतंजलि योग समिति के पदाधिकारियों से संपर्क कर भी पंजीयन करा सकते हैं। शिविर के अंत में भव्य समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें योग प्रदर्शन, नाटक (रामायण/महाभारत आधारित), बच्चों के प्रेरक भाषण, अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुति जैसी गतिविधियाँ विशेष आकर्षण होंगी।

## स्पर्धा में चयनित दो बालक व दो बालिका राष्ट्रीय स्पर्धा में छग का करेंगे प्रतिनिधित्व

*नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग*

छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के तत्वाधान में 2 एवं 3 मैं को अंडर 7 राज्य शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन रायपुर के बलबीर सिंग जुनेजा इनडोर स्टेडियम स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के कार्यालय में किया गया है। उक्त चैम्पियनशिप में चयनित दो बालक एवं दो बालिका अंडर 7 राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे।

स्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर 06 चक्रों में खेली जायेगी। स्पर्धा में प्रवेश शुल्क पांच सौ रुपए एवं बस्तर एवं सरगुजा संभाग के प्रतिभागियों के लिए 250 रुपए निर्धारित है। स्पर्धा में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। स्पर्धा के विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल एवं ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इंटरनेशनल आर्बिटर रॉकी देवांगन स्पर्धा के मुख्य निर्णायक होंगे। रजिस्ट्रेशन प्रभारी फीडे आर्बिटर अनिल शर्मा एवं आवास प्रभारी दीपांकर सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है।

# हरा सोना संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम, लगभग 920 करोड़ रुपए का होगा संभावित भुगतान

## तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में जुड़े 13 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार

*नई दृष्टिबिंदु / रायपुर*

छत्तीसगढ़ और अन्य वन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, जो आदिवासियों और वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है। हाल के नीतिगत बदलावों और सरकारी पहलों के कारण इन संग्राहकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है।

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों, विशेषकर आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 से प्रति मानक बोरा की दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ लाखों ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। वर्ष 2026 में राज्य के 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत 902 प्राथमिक समितियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य प्रस्तावित है। इस वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमान है। एक मानक बोरे में 1000 गड्डियां होती हैं और प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते शामिल रहते हैं।

### लगभग 11 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण होने की संभावना

बस्तर संभाग के 10 जिला यूनियनों की 216 समितियों में करीब 4 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अन्य 21 यूनियनों की 868 समितियों में लगभग 11 लाख मानक बोरा संग्रहण होने की संभावना है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। बस्तर संभाग में वर्ष 2025 के 3.90 लाख परिवारों की तुलना में इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 4.04 लाख हो गई है। इस साल अब तक 14 हजार 57 नए परिवार इस कार्य से जुड़े हैं।

### 10 नए फड़ और बेहतर तैयारी

नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में पहली बार 10 नए फड़ों की स्थापना की गई है, जहां 2100 से अधिक मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है। इसके अलावा सुकमा और केशकाल क्षेत्रों में भी नए फड़ जोड़े गए हैं। पिछले वर्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बाधाओं के कारण 351 फड़ों में संग्रहण नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष सभी फड़ों में कार्य शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

### सुगम संचालन और पारदर्शी भुगतान

संग्रहण कार्य को सुचारू बनाने के लिए संग्रहण कार्ड, बोरा, सुतली, गोदाम और परिवहन जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही तेन्दूपत्ता के भंडारण का बीमा भी कराया जा रहा है। संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।

### 920 करोड़ रुपये का संभावित भुगतान

इस वर्ष निर्धारित दर के अनुसार संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है। इससे ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। तेन्दूपत्ता संग्रहण को लेकर सरकार की यह पहल न केवल वनवासियों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

**खास खबर**

## राज्यपाल डेका से नो प्लास्टिक कैंपेन की ब्रांड एंबेसडर आप्टे ने की मुलाकात

*नई दृष्टिबिंदु / रायपुर*

राज्यपाल रमेन डेका से लोकभवन में नो प्लास्टिक अभियान की ब्रांड एंबेसडर श्रीमती शुभांगी आप्टे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने रायपुर नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों और जनजागरूकता गतिविधियों की जानकारी दी। श्रीमती आप्टे ने बताया कि अब तक वे स्कूलों, बैंकों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 55 हजार से अधिक कपड़े की थैलियों का वितरण कर चुकी हैं, ताकि लोगों को प्लास्टिक उपयोग से दूर किया जा सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि में 6 पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया है। साथ ही शासकीय अस्पतालों में जरूरतमंद माताओं और नवजात शिशुओं के लिए जच्चा-बच्चा किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यपाल ने उनके सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। ज्ञातव्य है कि श्रीमती आप्टे नगर निगम के स्वच्छता अभियान की ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

## वनांचल में विकास की नई रोशनी : मंत्री राजवाड़े के प्रयासों से दर्जनों टोलों के विद्युतीकरण को मंजूरी

**रायपुर।** प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से सूरजपुर जिले के वनांचल क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की दिशा में बड़ी पहल साकार हुई है। भटगांव विधानसभा क्षेत्र के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के दर्जनों गांवों और आश्रित टोलों के विद्युतीकरण के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े की पहल पर कोल्हुआ, महुली, करोटी, चोंगा सहित कई ग्राम पंचायतों के विभिन्न टोलों में विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत हुआ है। इसके अंतर्गत स्कूलपारा, हरिजनपारा, पांडोपारा, खासपारा, पहाड़पारा, मधवानीपारा, आमपारा और श्यामपारा जैसे क्षेत्रों में पहली बार नियमित विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इसके साथ ही कछवारी, खैरा, नवडीहा और कछिया जैसे अन्य क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। जिससे व्यापक स्तर पर ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी।

CSPDCL द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को प्रारंभ होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सूरजपुर के कार्यपालन अभियंता को सौंपी गई है, ताकि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित हो सके। वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की यह लंबे समय से प्रमुख मांग रही है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस विषय को प्राथमिकता में रखते हुए लगातार विभागीय स्तर पर समन्वय किया, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की लागत से 28 से अधिक विद्युतीकरण कार्यों को मंजूरी मिली। इस पहल से न केवल घरों में उजाला होगा, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और स्थानीय रोजगार एवं छोटे व्यवसायों को भी नई गति मिलेगी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंच रही है।

# ज्ञानभारतम् सर्वे को मिली रफ्तार : 31 मई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश

## समिति गठन, प्रशिक्षण और 'पांडुलिपि ट्रेजर हंट' जैसे नवाचारों पर जोर

*नई दृष्टिबिंदु / रायपुर*

मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि शासकीय संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, महाविद्यालयों एवं निजी संस्थानों में संरक्षित पांडुलिपियों के सर्वेक्षण के लिए सक्रिय प्रयास करें। उन्होंने कहा कि परंपरागत समुदायों और पुरातात्विक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और ज्ञान-संपदा मिल सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जनभागीदारी बढ़ाने के लिए 'पांडुलिपि ट्रेजर हंट' जैसे नवाचारों के आयोजन का सुझाव दिया गया, जिससे आम नागरिक भी इस अभियान से जुड़ सकें।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में 'ज्ञानभारतम्' राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वेक्षण अभियान समिति के सदस्य तथा सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण कार्य 31 मई तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि यह सर्वे केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि जिलों में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए है। साथ ही प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति का गठन, नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा सर्वेक्षण दलों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय पत्रकारों, साहित्यकारों, इतिहासकारों और जनप्रतिनिधियों को अभियान से जोड़ने पर बल दिया गया। यह अभियान पूरे देश के लिए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और उसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य के दौरान पांडुलिपियों के स्वामित्व अधिकारों का सम्मान, बिना अनुमति स्थानांतरण न करने और सभी गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया।

बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ज्ञानभारतम् पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत रूपरेखा, उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि शोधकर्ताओं के सहयोग से सुदूर अंचलों से भी पांडुलिपियों की महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की जा सकती है, जिससे इस अभियान को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी, संचालक संस्कृति श्री विवेक आचार्य सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

## 3147 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का काम शुरु, पत्थलगांव-झारखंड सीमा तक सड़क निर्माण ने पकड़ी गति

*नई दृष्टिबिंदु / रायपुर*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती पर रखी गई आधारशिला अब धरातल पर उतर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पत्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक 3147 करोड़ रूपये की लागत वाले मेगा परियोजना का निर्माण कार्य जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया है।

627 किलोमीटर लंबे रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल हिस्सा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। कुल लंबाई का लगभग 384 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में 104.250 किलोमीटर लंबे पत्थलगांव-झारखंड सीमा खंड पर निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। इस खंड में कुल 382 छोटी-बड़ी संरचनाएं बनाई जाएंगी, जो इस मार्ग को बाधारहित बनाएंगी। जिसमें 7 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 6 फ्लाईओवर और एक एलीवेटेड वायडक्ट स्ट्रक्चर, 10 वेहिकुलर अंडरपास, 18 लाइट वेहिकुलर अंडरपास, 26 स्मॉल वेहिकुलर अंडरपास, 11 ईओपी, 21 मवेशी एवं पैदल यात्री अंडरपास और 278 बॉक्स पुलिया का निर्माण किया जा रहा है।

कोरबा परियोजना इकाई के परियोजना निदेशक डी.डी. पालांवर ने बताया कि यह खंड रायपुर-धनबाद कॉरिडोर की रीढ़ है जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हमारा लक्ष्य इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना है। यह राजमार्ग छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी और व्यापारिक परिवहन को नई मजबूती देगा।

यह कॉरिडोर जशपुर जिले के लिए केवल सड़क नहीं, बल्कि लाइफलाइन साबित होगा। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह अंचल के महत्वपूर्ण नगरों-पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, दुलदुला और जशपुर को एक सूत्र में पिरोएगा। साथ ही, यह राजमार्ग रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जैसे औद्योगिक शहरों को सीधे झारखंड के धनबाद से जोड़कर व्यापारिक सुगमता प्रदान करेगा।

तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप ईंधन, यात्रा समय और कुल परिवहन लागत में बचत होगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कोयला खदानों एवं कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में स्थित प्रमुख इस्पात संयंत्रों के लिए बेहतर अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यातायात में सुगम आवागमन एवं दुर्घटनाओं और प्रदूषण में कमी होगी। वस्तुओं और खनिजों के कुशल परिवहन से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार व व्यावसायिक अवसरों का सृजन होगा।

# मंदिरों की जमीन पर उगा धान खरीदेगी सरकार? मुख्यमंत्री साय ने दिया बड़ा संकेत

*नई दृष्टिबिंदु / रायपुर*

अक्षय तृतीया पर छत्तीसगढ़ में मंदिरों की ताकत का बड़ा प्रदर्शन, धान खरीदी को लेकर सीएम का संकेत—बदल सकती है पूरी व्यवस्था! रायपुर में धार्मिक ऊर्जा और संगठन शक्ति का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने सीधे सत्ता के दरवाजे तक दस्तक दी, मंदिर महासंघ, छत्तीसगढ़ के भव्य शुभारंभ के साथ प्रदेश के मठ-मंदिरों को एक मंच पर लाने की ऐतिहासिक पहल हुई।

इसी के तुरंत बाद महासंघ का प्रतिनिधिमंडल सीधे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास पहुंचा जहां मंदिरों की जमीन पर उगने वाले धान के पंजीकरण और सरकारी खरीदी का बड़ा मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया, कार्यक्रम की शुरुआत माँ बम्लेश्वरी के

आशीर्वाद और संतों की उपस्थिति में हुई जहां साफ संदेश दिया गया कि अब मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि समाज निर्माण और मार्गदर्शन के केंद्र बनेंगे, पूरे प्रदेश से आए मंदिर न्यासों, धर्माचार्यों और हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि मंदिरों को संगठित कर उनकी आर्थिक और सामाजिक ताकत को मजबूत किया जाएगा, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने जो ज्ञापन रखा उसमें सबसे अहम मांग यही रही कि मंदिरों की कृषि भूमि से पैदा होने वाले धान को भी किसानों की तरह पंजीकृत किया जाए और सरकार उसे खरीदे, इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए साफ संकेत दिया कि मामला कैबिनेट तक जाएगा और जल्द निर्णय हो सकता है।

यही नहीं महासंघ ने बोनस की मांग भी उठाई ताकि मंदिरों की व्यवस्थाएं मजबूत हों और प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी सहायता भी सुनिश्चित की जाए, महासंघ के राष्ट्रीय संगठक सुनील घनवट और संयोजक मदन मोहन उपाध्याय ने साफ कहा कि आने वाले समय में मंदिरों में पुजारियों और न्यासियों का प्रशिक्षण होगा, मंदिरों की जमीन और संपत्ति का बेहतर उपयोग होगा और हर सक्षम मंदिर में गौशाला, यज्ञशाला, पाकशाला और पाठशाला जैसी व्यवस्थाएं फिर से खड़ी की जाएंगी ताकि सनातन परंपरा को जमीनी ताकत मिले, इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव समेत कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे जिन्होंने इस पहल को खुला समर्थन दिया, यह आयोजन सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की पटकथा जैसा नजर आया जहां धर्म, समाज और व्यवस्था को जोड़ने की कोशिश साफ दिखी, अब नि३३गाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं क्योंकि अगर मंदिरों के धान की खरीदी का रास्ता खुलता है तो यह प्रदेश की धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है—और यही इस पहल का सबसे बड़ा असर साबित हो सकता है।

# अक्षय तृतीया पर जिले में 10 बाल विवाह रोके गए, कलेक्टर के निर्देश पर सक्रिय रहा उड़नदस्ता दल

*नई दृष्टिबिंदु / रायपुर*

बाल विवाह मुक्त सूरजपुर की दिशा में जिला प्रशासन ने अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर पूरे जिले में प्रशासनिक अमले का उड़नदस्ता दल अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाहों पर सतत नजर बनाए हुए था, जिसके परिणामस्वरूप जिले में कुल 10 बाल विवाह समय रहते रोके गए।

### बाल विवाह मुक्त संकल्प

कलेक्टर एस. जयवर्धन ने बाल विवाह मुक्त सूरजपुर बनाने के उद्देश्य से जिले के समस्त विकासखण्डों में उड़नदस्ता दल गठित किए थे। अक्षय तृतीया के अवसर पर विवाहों की सघन जाँच के दौरान 10 स्थानों पर बाल विवाह होते पाए जाने पर परिजनों को समझाईश दी गई तथा विवाह रोकवाए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री शुभम बंसल इस दौरान सभी से संवाद कर यह सुनिश्चित करते रहे कि जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल समस्त उड़नदस्ता दलों, परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन की टीम के साथ सक्रिय रहकर कार्यवाही का मार्गदर्शन करते रहे।

### चार विकासखण्डों में कार्यवाही

अक्षय तृतीया के अवसर पर मात्र चार दिनों के भीतर विकासखण्ड रामानुजनगर से 02 बाल विवाह, विकासखण्ड भैयाथान से 04 बाल विवाह, विकासखण्ड प्रतापपुर से 02 बाल विवाह तथा विकासखण्ड ओडगी के बिहारपुर से 02 बाल विवाह रोके गए। रोके गए बाल विवाहों में 17 वर्षीय बालक एवं 14 वर्षीय बालिका भी शामिल हैं।

### अभिभावकों को दी गई जानकारी

समस्त प्रकरणों में बालिका एवं बालक के अभिभावकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं, अपितु एक गंभीर अपराध भी है। अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह कराने वाले, करने वाले एवं सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को 02 वर्ष की सजा एवं 01 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। परिजनों को यह संदेश भी दिया गया कि बालिका का विवाह तभी किया जाए जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। सभी स्थानों पर विवाह रोकने का पंचनामा, कथन एवं शपथ पत्र लिया गया तथा स्पष्ट किया गया कि इसके पश्चात यदि विवाह संपन्न किया गया तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी परिजनों की होगी।

### अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी

बाल विवाह रोकने की इस संयुक्त कार्यवाही में तहसीलदार गनहरण सिंह राठिया, जिला बाल संरक्षण इकाई से जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, परियोजना अधिकारी सुश्री अनुराधा आर्या, संरक्षण अधिकारी अखिलेश सिंह, विधिक सह परिविक्षा अधिकारी अमित कुमार भारिया, सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी साहू, आउटरीच वर्कर आरती राजवाड़े, चाइल्ड लाइन से जनार्दन यादव, प्रकाश राजवाड़े, दिनेश यादव, यशोदा गुप्ता, शीता सिंह, पर्यवेक्षक श्रीमती रत्यवती दास, श्रीमती गंगोत्री मानिकपुरी, श्रीमती सरवर्धा कुर्रे, श्रीमती शीला वर्मा, श्रीमती राधा कंवर, श्रीमती प्रभा, श्रीमती तारा पटेल, थाना प्रभारी रमकोला हीरालाल साहू, थाना प्रभारी चांदनी बिहारपुर आर. पी. साहू, एस.आई. छेत्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक अनिल कुजुर, आरक्षक प्रेम सिंह, भुनेश्वर सिंह, आरक्षक मनोज जायसवाल, ग्राम आरक्षक करथुला मिंज, अश्विन कुजुर, विजयी सिंह मरकाम, राम प्रसाद शांडिल्य, रामशंकर पौरे सहित सरपंच, सचिव एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

## संपादकीय

# नेतृत्व ने की गलती, कांग्रेस को बरसों सफाई देनी पड़ेगी

**राजनीतिक दल का नेतृत्व समझदार होता है, दूरदर्शी होता है, बड़े राजनीतिक फायदे और नुकसान को समझता है तो पार्टी को राजनीतिक नुकसान नहीं होता है, पार्टी के लोगों को सफाई नहीं देनी पड़ती है कि हमने ऐसा इसलिए नहीं किया। मुद्दा बहुत बड़ा होता है और बरसों तक जिसकी चर्चा होनी होती है तो राजनीतिक दल के नेताओं को बरसों सफाई देनी पड़ती है। महिला आरक्षण संशोधन मामले में कांग्रेस के नेतृत्व की गलती का खामियाजा अब बरसों कांग्रेस के राज्य नेताओं को भुगतना पड़ेगा और सफाई देनी पड़ेगी कि हम तो महिला आरक्षण चाहते हैं, जैसे ही कांग्रेस नेता सफाई देंगे हम तो महिला आरक्षण चाहते हैं तो महिलाएं तो सवाल पूछेंगी ही कि फिर आपने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का विरोध क्यों किया। देश की महिलाओं ने तो संसद में देखा है कि कांग्रेस व विपक्ष के विरोध के कारण महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ है। अब कांग्रेस नेता रोज सफाई देते रहें कि हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन महिलाएं इसे मानेंगी नहीं क्योंकि उन्होंने तो संसद में कांग्रेस नेतृत्व को विरोध करते देखा है। महिला आरक्षण के विरोध में वोट डालते देखा है और संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने पर कांग्रेस नेतृत्व को खुशी जाहिर करते देखा है।**

इसके बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी व पीएम मोदी की विश्वसनीयता का भी सवाल है कि देश की जनता किसकी बात पर ज्यादा यकीन करती है, देश की जनता पीएम मोदी की बातों पर ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि उनकी बात सीधी और साफ होती है और जनता को समझ में आती है कि पीएम मोदी उनके लिए क्या करने वाले थे और कांग्रेस ने उस काम को करने नहीं दिया। कांग्रेस सहयोग करती तो पीएम मोदी महिलाओं के आरक्षण का जो प्रयास करने वाले थे, वह हो जाता, वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सहयोग मांगने के बाद भी कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, विरोध किया और कांग्रेस के विरोध के कारण ही महिलाओं को जो 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 से मिलता और वह कई बरस बाद ही मिलेगा। महिलाओं का आरक्षण में मिलने वाली देरी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी व विपक्ष के नेता दोषी है, यह बात पीएम मोदी संसद के भीतर व राष्ट्र के नाम संबोधन में समझा चुके हैं और जनता को यह बात समझ में आ गई है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है तो उसके लिए कांग्रेस दोषी है।

पीएम मोदी भाजपा के सबसे बड़े नेता है और वह अपनी बात को जनता को समझाने में सफल रहते हैं, इसलिए वह ज्यादा लोकप्रिय भी है और उन पर जनता ज्यादा भरोसा भी करती है। राहुल गांधी अपनी बात जनता को समझा नहीं पाते हैं, वह जो कुछ कहते हैं कि जनता को समझ नहीं आता है। राहुल गांधी की बात कांग्रेस के नेता भी जनता को समझाने का प्रयास करते हैं तो जनता को समझ नहीं आता है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिर गया तो पीएम मोदी इसके लिए दुख व्यक्त करते हैं महिलाओं से माफी मांगते है और कहते हैं कि वह चाहते थे ऐसा हो लेकिन कांग्रेस ने सहयोग नही किया इसलिए हो नहीं सका। पीएम मोदी ने जनता को पहले ही बता दिया था कि यह काम कांग्रेस के सहयोग से ही होगा, उन्होंने इसके लिए संसद में जनता के सामने सहयोग मांगा और जनता ने देखा कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया जनता ने यह भी देखा की कांग्रेस व विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक गिरने पर मेजे थपथपा कर खुशी जाहिर की थी। इससे जनता को समझ आ जाता है कि कौन महिला आरक्षण के पक्ष में था और कौन विरोध में था।

पीएम मोदी ने संसद के भीतर व बाहर सरल शब्दों में देश के लोगों को बता दिया है कि हम महिलाओं को जल्द आरक्षण देना चाहते थे, इसके लिए प्रयास भी किया। विपक्ष से सहयोग मांगा विपक्ष ने सहयोग नहीं किया इसलिए महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। पीएम मोदी की बात ही देश की महिलाओं व लोगों को समझ आ गई है क्योंकि वह सीधी व सरल भाषा में है और उसे लोगों ने संसद में आंखों से देखा भी है। पीएम मोदी की बात को अब भाजपा को निचले स्तर पर गांवों तक पहुंचाना बहुत आसान है क्योंकि पीएम मोदी एक बार नहीं दो दो बार देश के करोड़ों लोगों तक अपनी यह बात पहुंचा चुके हैं कि वह तो महिला आरक्षण जल्द मिले चाहते थे, अगर वह आज नहीं मिला है तो कांग्रेस के कारण नहीं मिला है।

कोई राजनीतिक दल किसी मुद्दे को बड़ा मुद्दा तब ही बना पाता है जब उसका संगठन गांव गांव तक हो। अब भाजपा ने महिला आरक्षण के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है, राज्य स्तर छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में भी महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर जनआक्रोश रैली निकाली। फिर एक जनता को बताया गया कि महिलाओं का आरक्षण क्यों जल्द नहीं मिला। इसके बाद महिला आक्रोश सम्मेलन, मंडल स्तर पर पुतला दहन कर फिर लोगों का बताया जाएगा कि महिलाओं को भाजपा आरक्षण देना चाहती थी कांग्रेस के विरोध के कारण संभव नहीं हुआ। भाजपा के पास राम मंदिर जैसा कोई बड़ा मुद्दा अब तक नहीं था, पीएम मोदी ने भाजपा को राममंदिर जैसा बड़ा मुद्दा दे दिया है और भाजपा को उसे बड़ा मुद्दा अगले कई सालों में बनाना है और महिलाओं का बताना है कि उनका हितैषी कौन है और विरोधी कौन है। कांग्रेस नेतृत्व ने जो गलती की है, उसका खामियाजा आने वाले बरसों में कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। वह महिलाओं को सफाई देते रहेंगे कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं लेकिन महिलाओं का समझा नहीं पाएंगे।

# मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती रही

*अजीत द्विवेदी*

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार, 22 मार्च को 'इंडियन एक्सप्रेस' में अपने साप्ताहिक कॉलम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कटने वाले नामों के आंकड़े दिए, उस पर आधारित एक निष्कर्ष निकाला और एक दिलचस्प सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि लाखों वयस्क लोग, औसतन 10 फीसदी, मतदाता सूची से गायब हैं। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया, 'क्या गायब लोग वयस्क हैं, हां। क्या वे लोग नागरिक हैं, हां, जब तक कि इसके उलट कोई बात प्रमाणित नहीं होती है, फिर वे क्यों गायब हैं? बहुत दिलचस्प है यह सवाल। वे कह रहे हैं कि हर राज्य की वयस्क आबादी में से औसतन 10 फीसदी लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल किए जा रहे हैं और चूंकि उनको विदेशी या घुसपैठिया भी नहीं बताया जा रहा है फिर उनके नाम क्यों काटे जा रहे हैं?

उनके लेख के साथ आंकड़ों की टेबल है, जिसमें बताया गया है कि एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के मुकाबले एसआईआर के बाद की मतदाता सूची में बिहार में छह फीसदी, छत्तीसगढ़ में 12 फीसदी, केरल में साढ़े तीन फीसदी, मध्य प्रदेश में छह फीसदी, राजस्थान में छह फीसदी, तमिलनाडु में साढ़े 12 फीसदी नाम कटे हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार में पहले कुल वयस्क आबादी में से 96.7 फीसदी लोगों के नाम मतदाता सूची में थे, जबकि एसआईआर के बाद आई सूची में 90.7 फीसदी लोगों के नाम हैं। यानी वयस्क आबादी में से 9.3 फीसदी लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने सात राज्यों के आंकड़े दिए हैं।

सबसे दिलचस्प आंकड़ा उनके अपने राज्य तमिलनाडु का है। एसआईआर से पहले तमिलनाडु की वयस्क आबादी के मुकाबले 106.8 फीसदी नाम मतदाता सूची में थे और अब 94.3 फीसदी हैं। उम्मीद थी कि टेबल में दिए गए इस आंकड़े की वे कुछ व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि अनुमानित वयस्क आबादी से करीब सात फीसदी ज्यादा मतदाता तमिलनाडु की मतदाता सूची में कैसे थे और इनके नाम कट गए तो ये लोग क्लेम करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

पी चिदंबरम ने अपने लेख में यह बताने की कोशिश की है और बड़े मासूम तरीके से की है कि हर राज्य में जितने वयस्क नागरिक हैं लगभग उतने नाम मतदाता सूची में होने चाहिए। सवाल है कि क्या वे इतने नासमझ हैं कि मौजूदा समय के बदलावों को नहीं समझ रहे हैं? क्या देश के अंदर और बाहर हुए पलायन या प्रवासन की परिघटना को चिदंबरम नहीं समझते हैं? क्या वे जनगणना में होने वाली गड़बड़ियों और गिनती में दोहराव की संभावना को नहीं समझते हैं? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक 2023 में भारत में प्रवासन की दर 28.88 फीसदी थी। यह 2011 के मुकाबले लगभग 12 फीसदी कम थी। फिर भी संख्या के लिहाज से देखें तो देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मूल निवास से दूर किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में रहते थे।

विवेक देबरॉय और देवी प्रसाद मिश्र द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 75 फीसदी के करीब लोग पांच सौ किलोमीटर के दायरे में गए थे। इसे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कहा गया है। करीब 25 फीसदी लोग पांच सौ किलोमीटर के दायरे से बाहर थे। यानी लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे थे, जो अपने मूल निवास से पांच सौ किलोमीटर दूर जाकर रहते थे। वे काम के सिलसिले में गए या कारोबार के सिलसिले में या शिक्षा के लिए गए यह अलग बात है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरेलू प्रवासन के अलावा लगभग साढ़े तीन करोड़ भारतीयों ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन किया है। यानी विदेश में रहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल करीब 25 लाख लोग भारत से विदेश जा रहे हैं। अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश के करीब एक करोड़ 10 लाख लोग देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जबकि बिहार के 60 लाख लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 14 लाख लोग झारखंड में रहते हैं।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कट रहे नामों के आधार पर पी चिदंबरम ने एक एकपक्षीय निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने इसके दूसरे पहलुओं की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझी है। जैसे घरेलू और विदेशी प्रवासन के आंकड़े को उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। अगर घरेलू प्रवासन करने वाले 40 करोड़ और विदेश में रहने वाले साढ़े तीन करोड़ लोगों में से एक चौथाई भी अपने मूल निवास की बजाय दूसरी जगह मतदाता बन गए हैं तब भी यह संख्या लगभग 11 करोड़ होगी। वास्तविक संख्या निश्चित रूप से इससे ज्यादा होगी। इसी तरह उन्होंने इस संभावना को भी संज्ञान में नहीं लिया है कि अनुमानित वयस्क आबादी क्या सचमुच उतनी है जितनी बताई जा रही है या मतदाता सूची में जितने नाम शामिल हो रहे हैं उतनी ही वयस्क आबादी है?

ध्यान रहे आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी उसके बाद के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, जिनके बारे चिदंबरम ने लिखा है कि आजकल इतने आधुनिक टूल्स आ गए हैं कि अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर खुले दिमाग से सोचें तो यह सवाल तो उठ सकता है कि 2011 में जनगणना ज्यादा गंभीरता से, गहराई से और ज्यादा दस्तावेजों की जांच करके हुई थी या आज एसआईआर का काम ज्यादा गंभीरता से हो रहा है? बहुत संभव है कि जनगणना के आंकड़ों में कमी हो, गिनती में दोहराव हुआ हो और एसआईआर के बाद बन रही सूची वास्तविकता के ज्यादा नजदीक हो। पूरी तरह से परफेक्ट होने की बात कोई नहीं कह सकता है।

अगर वे इन बातों का संज्ञान लेते और औसतन 60 से 70 फीसदी वोट पड़? की वास्तविकता के साथ उसको मिला कर देखते तब उनको निश्चित रूप से समझ में आता कि राज्यों की मतदाता सूचियां घोस्ट मतदाताओं से भरी हैं और इसलिए तमाम प्रयास के बावजूद ज्यादातर राज्यों में मतदान का प्रतिशत नहीं सुधरता है। अभी तक एसआईआर के बाद सिर्फ एक राज्य में चुनाव हुआ है और वह राज्य है बिहार। बिहार में एसआईआर से पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में 57 फीसदी से कुछ ज्यादा मतदान हुआ था, जबकि एसआईआर के बाद 2025 में 67 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ। करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। अगर चिदंबरम साहेब यह सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार की अनुमानित वयस्क आबादी के 91 फीसदी का ही नाम मतदाता सूची में क्यों शामिल है बाकी नौ फीसदी लोग कहां हैं तो साथ ही यह भी पूछना चाहिए कि 67 फीसदी ने ही वोट क्यों डाला, बाकी 33 फीसदी कहां हैं? जाहिर है कि अब भी बिहार की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं, जो बिहार में नहीं रहते हैं और उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने दूसरी जगह भी मतदाता पहचान पत्र बनवा रखा होगा।

ऐसे ही पी चिदंबरम ने इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया कि जिन लोगों के नाम कट रहे हैं अगर उन्हें काटने का आधार सही है तो फिर इनके नाम मतदाता सूची में क्यों थे और उसका लाभ किसको मिल रहा था? यह बहुत जरूरी सवाल है कि मतदाता सूची में मृत लोगों का या दूसरी जगह पर शिफ्ट कर गए लोगों या एक से ज्यादा जगह मतदाताओं के नाम होने का लाभ किसको मिलता है? इसका एक निश्चित जवाब नहीं है लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि हर राज्य में सत्तारूढ़ दल को इसका लाभ मिलेगा। यह भी कह सकते हैं कि अपने अपने असर वाले मजबूत इलाकों में अलग अलग पार्टियां इसका लाभ उठाती होंगी।

इसका अर्थ है कि दशकों से भारत में मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती रही है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से सही है या इससे हर किस्म की गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। परंतु यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि एसआईआर से मतदाता सूचियों की काफी हद तक सफाई हुई है। उनमें शुद्धता आई है। मृत लोगों या स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए लोगों या एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में शामिल लोगों के नाम काटे गए हैं। ऐसे कुछ लोगों के नाम हो सकता है कि अब भी सूची में शामिल हो और या कुछ सही लोगों के नाम भी कट गए हों लेकिन एसआईआर को लेकर पी चिदंबरम जो सवाल उठा रहे हैं वह पूरी तरह से राजनीतिक है, एकपक्षीय है, पूर्वाग्रह से प्रभावित है और उसका जमीनी वास्तविकताओं या आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। वह उनके और उनके नेता के बनाए नैरेटिव का हिस्सा भर है।

# होर्मुज स्ट्रेट के खुलने से खाड़ी में शांति के संकेत

**होर्मुज स्ट्रेट के खुलने ईरान का होर्मुज स्ट्रेट को सभी कमर्शल जहाजों के लिए पूरी तरह खोल देना वैश्विक व्यापार के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर है। इससे इस संकरे समुद्री मार्ग को लेकर पिछले डेढ़ महीने से जारी तनाव कम होगा। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी लगातार संकेत आ रहे हैं कि समझौता हो सकता है।**

बड़ी बाधा दूरः अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध की जितनी बड़ी वजह तेहरान का परमाणु कार्यक्रम है, उतनी ही बड़ी वजह होर्मुज भी बन चुका है। दोनों के बीच पहले दौर की वार्ता असफल होने के पीछे एक बड़ी वजह होर्मुज भी था। इसके अलावा लेबनान पर जारी इस्राइली हमलों के कारण बातचीत बेहद अविश्वास भरे माहौल में हुई थी। अब इस्राइल और लेबनान 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, तो ईरान ने भी होर्मुज को खोल दिया।

सही होगा माहौलः यह खबर भी सकारात्मक है कि सोमवार से जारी अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी के बीच शुक्रवार को पहली बार ईरान के एक ऑयल शिपमेंट ने खाड़ी को पार किया। ये सारे डिवेलपमेंट इस समझौते की दिशा में अहम कदम हैं। इससे बातचीत के लिए सही माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह जरूरी है कि अब किसी पक्ष को माहौल खराब करने की छूट न दी जाए। हिजबुल्लाह जैसे तत्वों से भी सावधान रहना होगा, जो संघर्ष बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं।

ट्रंप के दावेः अमेरिका और ईरान के बीच इस समय दूसरे दौर की वार्ता के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दिन पहले दो बड़े दावे किए। पहला, ईरान युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है और दोनों देश शांति समझौते के करीब हैं। उनका दूसरा दावा ज्यादा दिलचस्प है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला समृद्ध यूरेनियम सौंपने पर सहमत हो गया है। युद्ध छेड़ने के बाद से ट्रंप ने संघर्ष और शांति को लेकर इतने अलग-अलग दावे किए हैं कि उनमें से किसी एक पर यकीन कर पाना मुश्किल है। इसके बावजूद इधर उनके बयान इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका इस जंग को खत्म करना चाहता है।

नुकसान का असरः यह युद्ध रुकना ही चाहिए। इंटरनैशनल एनर्जी एजेंसी ने चेताया है कि पश्चिम एशिया में हुए नुकसान की वजह से तेल उत्पादन को युद्ध के पहले वाली स्थिति में लाने में लगभग दो साल लग जाएंगे। यानी, अगर कोई समझौता होता है, तो भी दुनिया को झटके से उबरने में लंबा समय लगेगा। इसलिए अगर अब बात कुछ बनती दिख रही है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए।

## सू- दोकू क्र.016

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 6 | | 8 | | 3 | |
| 9 | | 8 | | 3 | | 4 | | |
| | | | | | | | 5 | |
| 5 | | 2 | | | 7 | | 6 | |
| | 8 | | 4 | | | 1 | | 3 |
| | | | | 9 | | | | |
| 8 | | | 9 | | | | 1 | |
| | 5 | | | 1 | | 6 | | 2 |
| | | 1 | 7 | | | | 4 | |

**नियम**

1. कुल 81 वर्ग है, जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

**सू-दोकू क्र.015 का हल**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 |
| 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | | 6 | 2 |
| 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 |

# ट्रैक से संसद तक : क्यों भारत के भविष्य का नेतृत्व महिलाओं को करना चाहिए

*डॉ. पीटी ऊषा*

**मैंने अपना पूरा जीवन भागदौड़ में ही बिताया है, पहले केरल की कच्ची सड़कों पर, फिर वैश्विक मंचों पर और अब सार्वजनिक जीवन के गलियारों में। हर कदम पर मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अनकही बाधाओं का भी, जिन्होंने महिलाओं को यह बताया कि उनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। मैंने यह भी देखा है कि जब ये बाधाएं टूटने लगती हैं तो क्या होता है। अवसर परिणामों को बदल देता है और इससे भी जरुरी बात यह है कि यह लोगों की सोच को बदल देता है।**

यही कारण है कि संविधान (एक सौ आईसवाँ संशोधन) विधेयक, 2023—नारी शक्ति वंदन अधिनियम—केवल एक विधायी उपलब्धि नहीं है। यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित संरचनात्मक सुधार है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना न तो कोई रियायत है और न ही दिखावा। यह अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी लोकतंत्र की दिशा में एक जरुरी कदम है।

### खेलों ने हमें क्या सिखाया है

जब मैंने 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में हिस्सा लिया और कुछ ही सेकंड के अंतर से पदक से चूक गई, तब बहुत कम भारतीय लड़कियां थीं, जो वैश्विक मंच पर खुद को देख पाती थीं। लेकिन पिछले कई दशकों में यह स्थिति बदली है। प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और पहचान तक पहुंच में सुधार के साथ, भारतीय महिलाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता हासिल करने लगीं है। पी.वी. सिंधु, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट और मैरी कॉम जैसी एथलीटें अकेले नहीं उभरीं। वे एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम हैं, जिसने धीरे-धीरे ही सही, पहुंच को व्यापक बनाना शुरू किया। प्रतिनिधित्व आकांक्षाएं पैदा करता है और आकांक्षा, जब समर्थित होती है, तो उपलब्धि दिलाती है। सबक साफ है। जब महिलाओं को स्थान दिया जाता है, तो वे व्यवस्था में केवल भाग नहीं लेतीं, वे शानदार प्रदर्शन भी कर दिखाती हैं।

### हर भारतीय के लिए बेहतर शासन

भारत में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व का प्रभाव पहले ही देखा जा चुका है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किए जाने के बाद से, विभिन्न राज्यों में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व वाले क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार हुआ है। ये महज "महिलाओं के मुद्दे" नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। महिला नेता अक्सर सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, सुचारू रूप से चलने वाले स्कूल, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी शासन से जुड़ी उन रोजमर्रा की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो परिवारों और समुदायों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। इस प्रतिनिधित्व को राज्य विधानसभाओं और संसद तक विस्तारित करना केवल निष्पक्षता की बात नहीं है। यह शासन की गुणवत्ता में सुधार से जुड़ा है।

### प्रतिनिधित्व का आर्थिक महत्व

भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी विश्व में सबसे कम है, जो लगभग 25 प्रतिशत के आसपास है। यह केवल एक सामाजिक चिंता नहीं, बल्कि एक आर्थिक समस्या भी है। विधानसभाओं में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व उन नीतियों को प्राथमिकता देने में मदद कर सकता है, जो इस अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती हैं, जैसे किफायती बाल देखभाल, सुरक्षित कार्यस्थल, ऋण तक पहुंच और महिला उद्यमियों के लिए समर्थन। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से भारत की जीडीपी में 700 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है। अधिक समावेशी संसद

न केवल एक लोकतांत्रिक आवश्यकता है, बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता भी है।

### सुरक्षा, गरिमा और भागीदारी

भारत भर में लाखों महिलाओं के लिए, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी अभी भी सुरक्षा, भेदभाव और असमान पहुंच की चिंताओं से प्रभावित है। चाहे खेल हो, शिक्षा हो या कार्यस्थल, ये समस्याएं हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं।

संसद में अधिक महिलाओं का मतलब है कि कानून और नीतियां महज समझ से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की हकीकत से आकार लेती हैं। इसका मतलब है प्रवर्तन के लिए मजबूत वकालत, सहायता प्रणालियों के लिए संसाधनों का बेहतर आवंटन और एक न्याय ढांचा, जो उत्तरदायी और सुलभ हो। शासन तभी अधिक प्रभावी होता है, जब वह उन लोगों के अनुभवों को दर्शाता है, जिनकी वह सेवा करता है।

### प्रतिनिधित्व और आकांक्षाओं की शक्ति

भारत में सत्ता की छवि लंबे समय से मुख्य रूप से पुरुष प्रधान रही है। उस छवि को बदलना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह एक बदलावकारी प्रक्रिया है। जब मणिपुर, झारखंड, राजस्थान या भारत के किसी भी हिस्से की कोई युवती अपने जैसी दिखने वाली, अपने जैसी बोलने वाली और समान पृष्ठभूमि से आने वाली किसी महिला को देश के कानूनों को आकार देते हुए देखती है, तो यह सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि यह संभावनाओं के प्रति उसके विश्वास को भी बदल देती है।

आकांक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का आधार है। विधानसभाओं में आरक्षण से स्तर कम नहीं होता, बल्कि अवसरों का दायरा बढ़ता है। भारत की महिलाओं ने खेल जगत, सशस्त्र बलों, विमानन और व्यावसायिक पदों पर पहले ही कई बाधाओं को पार कर लिया है। विधायी प्रतिनिधित्व इस यात्रा का स्वाभाविक अगला कदम है।

### अब है कार्यवाही का वक्त

राज्यसभा में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करने के बाद, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कैसे विविध दृष्टिकोण बहस और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। फिर भी, आज लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल लगभग 15 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। अब बस इसे पूरी तरह, निष्ठापूर्वक और बिना देर किए लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरुरत है।

भारत अपनी आधी आबादी को सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकायों में कम प्रतिनिधित्व देते हुए, विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा नहीं रख सकता। आधी प्रतिभा को दरकिनार करके विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता, न ही आधी आवाज पर सच्चा लोकतंत्र फल-फूल सकता है। आगे का रास्ता साफ है। सवाल यह है कि क्या हम उस पर चलने का दृढ़ संकल्प रखते हैं।

**(लेखक राज्यसभा सांसद, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल खेल संघ, भारत की अध्यक्ष हैं।)**

# कलेक्टर के निर्देश पर एम्बुलेंस की हुई तैनाती, लेमरू में दौड़ी जिंदगी की नई रफ्तार

## संजीवनी 108 सेवा से ग्रामीणों को मिल रहा त्वरित उपचार

*नई दृष्टिबिंदु / कोरबा*

कोरबा जिले के अत्यंत दुर्गम वनांचल लेमरू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जिला मुख्यालय से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर स्थित यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण है और यहां विशेष रूप से संरक्षित पिछड़ी जनजातियों जैसे पहाड़ी कोरवा और बिरहोर की बड़ी आबादी निवास करती है। लंबे समय तक यह इलाका स्वास्थ्य सुविधाओं से लगभग कटा रहा, जहां किसी भी आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में 5 से 6 घंटे का बहुमूल्य समय लग जाता था। कई बार समय पर उपचार नहीं मिलने से स्थिति गंभीर हो जाती थी।

प्रशासन ने इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए लेमरू क्षेत्र में संजीवनी एक्सप्रेस 108 एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की है। कलेक्टर कुणाल दुदावत की पहल और मार्गदर्शन में शुरू हुई यह सेवा अब इस वनांचल क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस यह एंबुलेंस अब एक फोन कॉल पर गांवों तक पहुंच रही है और मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध करा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू के अंतर्गत आने वाले लगभग 20 गांवों की 16 हजार से अधिक आबादी को इस सेवा का सीधा लाभ मिल रहा है। इनमें 1700 से अधिक लोग विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित हैं। गढ़उपरोड़ा, देवपहरी, अरसेना, नकिया और लेमरू, रापा, बड़गांव, छातीबहार, लामपहाड़, डोकरमना, विमलता जैसे दूरस्थ गांव अब इस सेवा से सीधे जुड़े हैं, जिससे यहां के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। संजीवनी 108 एंबुलेंस केवल मरीजों को लाने-ले जाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक चलती-फिरती जीवनरक्षक इकाई के रूप में काम कर रही है। इसमें फोल्डेबल और कैनवास स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सिलिंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी और शुगर जांच उपकरण, बर्न किट, डिलीवरी किट, सक्शन मशीन और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था उपलब्ध है। गंभीर मरीजों के लिए एएलएस सुविधा के अंतर्गत वेंटिलेटर भी लगाया गया है और प्रशिक्षित ईएमटी स्टाफ हर समय सेवा के लिए तत्पर रहता है। पिछले एक वर्ष में इस सेवा के माध्यम से लगभग 1200 मरीजों को समय पर उपचार मिल चुका है। हृदयघात, सड़क दुर्घटनाएं, सपर्दंश, प्रसव संबंधी जटिलताएं और मलेरिया-डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों में यह सेवा कई लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। पहले जहां मरीजों को चारपाई पर ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ता था, वहीं अब एंबुलेंस की सायरन सुनते ही ग्रामीण रास्ता बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सेवा किसी की जान बचाने आई है।

कोरबा जिले को हाल ही में 12 नई संजीवनी 108 एंबुलेंस प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक को विशेष रूप से लेमरू क्षेत्र में तैनात किया गया है। जिले में पहले से 11 पुरानी 108 और 14 महतारी 102 एंबुलेंस सेवाएं संचालित हैं, जिससे संपूर्ण जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत हुई है। लेमरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के कारण पहले ही राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। अब संजीवनी 108 सेवा के जुड़ने से यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो गई है तथा दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराना संभव हो पाया है। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवारों को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दुर्गम रास्तों और संसाधनों की कमी के कारण निजी वाहन का खर्च उठाना उनके लिए कठिन था। अब सरकारी एंबुलेंस सेवा के माध्यम से उन्हें बिना किसी अतिरिक्त बोझ के त्वरित चिकित्सा सहायता मिल रही है।

**खास खबर**

## शासकीय भूमि से हो रहा था अवैध खनन, एक पोकलेन और 3 हाइवा जब्त

*नई दृष्टिबिंदु / मुंगेली*

मुंगेली जिले में अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि से अवैध खनन में संलिप्त एक पोकलेन मशीन और तीन हाइवा वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में मुंगेली विकासखंड के ग्राम अमरटापू (मोतिमपुर) क्षेत्र में बिना अनुमति खनन कार्य संचालित पाया गया।

जानकारी के अनुसार मुंगेली एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान शासकीय भूमि पर अवैध रूप से खनिज उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित मशीनरी एवं वाहनों को जब्त कर लिया गया।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

## मंत्रालय में सिविल सर्विस डे मनाया गया

**रायपुर।** मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सिविल सर्विस दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को पहुँचाने का कार्य



किया जा रहा है। शासन की अधिक से अधिक सेवाओं को लोक सेवा गांरटी सेवा के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन की करीब 750 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के तहत अधिसूचित किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 21 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देशभर के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं विभागों को पुरस्कृत किया जाता है। पूर्व मुख्य सचिव सुयोग्य कुमार मिश्रा ने सिविल सर्विस दिवस के मौके पर प्रशासन की विविध क्षेत्रों में कार्य करने एवं महत्वता के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह भी विशेष रूप से शामिल हुए। सुशासन एवं अभिसरण विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने मुख्यमंत्री हेल्प लाईन के बारे में लोगों द्वारा विविध माध्यम से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत दर्ज कराने एवं निराकरण के प्रबंधन एवं सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने ई-डिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, सामान्य प्रशासन एवं उद्योग वाणिज्य विभाग के सचिव रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के सचिव और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी संभागायुक्त एवं जिलों के कलेक्टर शामिल हुये।

# नई सोच और नई कार्य पद्धति से शहरों व लोगों के कल्याण के लिए करें काम-मंत्री अरुण साव

## शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से लगाएं रोक

*नई दृष्टिबिंदु / रायपुर*

प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आज दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बेतरतीब निर्माणों, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने को कहा। श्री साव ने कहा कि काम में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को नई सोच और नई कार्य पद्धति से शहरों तथा शहरवासियों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। उन्होंने राज्य के उभरते शहरों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पांचों संभागों के विभागीय क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को हर तिमाही में प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत का व्यक्तिगत निरीक्षण कर संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ शशांक पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को आगामी 31 मई तक नगर पंचायतों की नई संपत्तियों पर करारोपण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण बढ़ाने संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज जैसे करों की वसूली गंभीरता और कड़ाई से करने को कहा। उन्होंने एनर्जी ऑडिट के माध्यम से गैर-जरूरी विद्युत कनेक्शनों की पहचान कर इसके विच्छेदन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकाय के सभी कामिर्कों को हर माह समय पर वेतन और बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा।

श्री साव ने जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित करते हुए शत-प्रतिशत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराने को कहा। उन्होंने 31 मई तक बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने को कहा। श्री साव ने सभी सीएमओ को मुख्यालय में ही निवास करते हुए प्रतिदिन प्रातः भ्रमण कर शहर की साफ-सफाई और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अपने साथ रखने को कहा। उन्होंने सीएमओ द्वारा प्रातः भ्रमण में की जा रही कोताही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए रोजाना अनिवार्यतः कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए।

श्री साव ने शहरों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए बच्चों के लिए खेल के मैदानों और उद्यानों के लिए जगहों का चिन्हांकन करने को कहा। उन्होंने कुनकुरी और अंबागढ़-चौकी में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों का निर्माण इस साल दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर दूरदशिर्ता से काम करते हुए अगले दस वर्षों के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता में रखते हुए इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि से पुख्ता व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने वर्षा ऋतु के पहले सभी नाला, नालियों, ड्रेनेज और तालाबों की सफाई करने को कहा। उन्होंने पाइपलाइन्स के लीकेज ठीक करते हुए सभी घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण एक साल के भीतर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि शहर के जरूरतमंदों के लिए पीएम आवास स्वीकृत करना और बनवाना सीएमओ की जिम्मेदारी है। इस पर सक्रियता और गंभीरता से काम करते हुए आवास स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने को कहा। उन्होंने आवास की स्वीकृति के बाद लाभाथिर्यों को बुलाकर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान सहित योजना से संबंधित सभी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में प्रदेशभर में आगामी 1 मई से शुरू हो रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शहरवासियों को लाभान्वित करने की तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता राजेश शर्मा और नगर पंचायतों के अभियंता भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

**इन कार्यों और योजनाओं की हुई समीक्षा**

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिनभर चले मैराथन बैठक में नगर पंचायतों में राजस्व वसूली, विद्युत देयकों के भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास व 15वें वित्त आयोग के कार्यों, नालंदा परिसरों, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाओं, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट कर्मयोगी तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा की।

# पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में सूरजपुर बना प्रदेश में प्रथम स्थान पर

**आवास प्लस 2 .0 के तहत 1 .40 लाख से अधिक परिवारों का नवीन सर्वे भी सफलतापूर्वक पूरा किया**

*नई दृष्टिबिंदु / सूरजपुर*



प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के प्रभावी क्रियान्वयन ने ग्रामीण भारत में आवास परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे सभी के लिए आवास का सपना साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन में विगत दो वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024-26) में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कुशल निर्देशन एवं सतत मॉनिटरिंग और समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ने पारदर्शी तरीके से लाभाथिर्यों को सीधे सहायता प्रदान करके और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर ग्रामीण राज्य में आवास की कमी को कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जिले में कुल 72 हजार 368 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए थे, इनमें से अब तक 63 हजार 947 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जो कि 88.36 प्रतिशत की प्रभावशाली उपलब्धि को दर्शाता है। यह आंकड़ा न केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम भी है।

वित्तीय प्रबंधन के स्तर पर भी सूरजपुर जिला राज्य में अग्रणी रहा है। आवास निर्माण के लिए निर्धारित 868.42 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 809.23 करोड़ रुपये, अर्थात 93.18 प्रतिशत राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जा चुकी है, इससे पारदशिर्ता सुनिश्चित हुई है और निर्माण कार्य में तेजी आई है। इसके साथ ही, जिले में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवास प्लस 2.0 के तहत 1.40 लाख से अधिक परिवारों का नवीन सर्वे भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिससे आने वाले समय में और अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

जिला प्रशासन की सक्रियता, जमीनी स्तर पर निरंतर निगरानी और हितग्राहियों की सहभागिता ने इस योजना को एक जन-आंदोलन का रूप दे दिया है। सूरजपुर जिले के हजारों परिवार अपने पक्के घर का सपना साकार होते देख रहे हैं।

# जग्गी हत्याकांड : अमित जोगी को एससी से मिली राहत, सरेंडर पर रोक : सीबीआई से मांगा जवाब

*नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-दिल्ली*

बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है। वहीं, अगली सुनवाई तक अमित जोगी के सरेंडर करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

अमित जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला, जिसमें उइक को अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा, हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अब दोनों मामले की एक साथ सुनवाई हुई। इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को अमित जोगी को IPC की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी गई थी। 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

## बिलासपुर से दिल्ली हवाई सफर हुआ सुहाना

बिलासपुर। हवाई यात्रियों के लिए अलायंस एयर ने समर शेड्यूल जारी कर दिया है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने अलायंस एयर द्वारा जारी किए गए समर शेड्यूल के अनुसार, अब दिल्ली की उड़ान सप्ताह में 5 दिन से घटाकर चार दिन कर दी गई है। वही वहीं प्रयागराज एक और कोलकाता उड़ान सप्ताह में दो दिन उपलब्ध रहेगी। नया समर शेड्यूल एक मई से लागू होगी। नए शेड्यूल के अनुसार दिल्ली से बिलासपुर और आगे अंबिकापुर जाने वाली उड़ानों के समय में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बदलाव है। रविवार को दिल्ली, प्रयागराज बिलासपुर सेक्टर में नई उड़ान फ्रीक्वेंसी जोड़ी गई है।

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202604101000104**

**विषयः- अ-6 अ मामले की श्रेणीः- राजस्व**
कोहका प.ह.न. 00045 [(हे0)]
अनावेदक पक्षकार -

**ईश्तहार**

सनः-2025-2026
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार दीप्ती देवहारे,
अनावेदक पक्षकार-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीप्ती देवहारे पिता/पति/विभाग-यादव राम पता-भिलाई द्वारा ग्राम- कोहका प.ह.न. 46 रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. 2047/66 रकबा 0.0140 आवेदिका के माता के नाम पर दर्ज था किन्तु उक्त भूमि वर्तमान पटवारी अभिलेख में आवेदक के स्थान पर विक्रेता का नाम दर्ज हो जाने एव क्रेता आवेदक की माता की मित्यु हो जाने के कारण विक्रेता का नामा विलोपित कर क्रेता के विधिक वारिसानो का नाम दर्ज किये जाने जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 05.05.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 16/04/2026 को जारी किया जाता है।

**डिकेशवर साहू**
**अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर**

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202604101000108**

**विषयः- अ-6 अ मामले की श्रेणीः- राजस्व**
कोहका प.ह.न. 00046 [(हे0)]
अनावेदक पक्षकार -

**ईश्तहार**

सनः-2025-2026
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार राधिका यादव
अनावेदक पक्षकार-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राधिका यादव पिता/पति/विभाग- कपिल राम यादव पता-भिलाई द्वारा ग्राम- कुरुद प.ह.न. 46 रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. 1313/70 रकबा 0.007 हे./812.50 वर्गफीट आवेदिका के नाम पर दर्ज है, किन्तु उक्त भूमि वर्तमान पटवारी अभिलेख में आवेदक के स्थान पर .... प्रदर्शित हो रहा है। जिसे त्रुटि सुधार किए जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/04/2026 को जारी किया जाता है।

**डिकेशवर साहू**
**अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर**

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202604101000005**

**विषयः- अ-6 अ मामले की श्रेणीः- राजस्व**
कोहका प.ह.न. 00045 [(हे0)]
अनावेदक पक्षकार -

**ईश्तहार**

सनः-2025-2026
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार शांति मिश्रा
अनावेदक पक्षकार-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शांति मिश्रा पिता/पति/विभाग- देवी प्रसाद पता-कोहका द्वारा ग्राम- कोहका प.ह.न. 45 रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. पुराना 442/1, 443/1 का टू. रकबा 0.007 0.022 हे. है जिसका नया ख.न. 5127 दर्ज हुआ जिसमें खसरा क्रमांक 442/124, 143/11 तथा 442/145, 443/111 रकबा 0.022, 0.007 हे. वर्तमान पटवारी अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण त्रुटि सुधार किए जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 11.05.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20/04/2026 को जारी किया जाता है।

**डिकेशवर साहू**
**अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर**

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202604101000107**

**विषयः- अ-6 अ मामले की श्रेणीः- राजस्व**
कोहका प.ह.न. 00046 [(हे0)]
अनावेदक पक्षकार -

**ईश्तहार**

सनः-2025-2026
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार नरेन्द्र कुमार यादव
अनावेदक पक्षकार-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेन्द्र कुमार यादव पिता/पति/विभाग-मनोहर यादव पता-भिलाई द्वारा ग्राम- कुरुद प.ह.न. 46 रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. 1313/69 रकबा 0.07 हे./831.50 वर्गफीट आवेदिका के नाम पर दर्ज है, किन्तु उक्त भूमि वर्तमान पटवारी अभिलेख में आवेदक के स्थान पर .... प्रदर्शित हो रहा है। जिसे त्रुटि सुधार किए जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/04/2026 को जारी किया जाता है।

**डिकेशवर साहू**
**अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर**

## निधन

### बलराम सिंह वशिष्ठ

**भिलाई।** वैशाली नगर (चंद्रनगर) भिलाई निवासी भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिव्रत कर्मचारी 76 वर्षीय बलराम सिंह वशिष्ठ का निध्धन बुधवार 22 अप्रैल को बैतूल में हो गया है। वे लम्बे समय से बीमार थे। उनकी अंतिम यात्रा चंद्रनगर सड़क 25 निज निवास से 23 अप्रैल को दोपहर 01 वाजे रामनगर मुक्तिधाम के लिए निकली जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वे लीला धर वशिष्ठ के छोटे भाई और प्रतिमा, छवि, कनु एवं हितेष वशिष्ठ के पिता थे।

## टोविनो थॉमस ने जूनियर एनटीआर की 'ड्रैगन' का हिस्सा होने पर दी प्रतिक्रिया

निर्देशक प्रशांत नील की जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म, जिसे अभी 'ड्रैगन' के नाम से जाना जा रहा है, अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चाओं में है। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ मलयालम स्टार टोविनो थॉमस के भी होने की चर्चाएं चल रही थीं। लेकिन अब टोविनो थॉमस ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। टोविनो फिल्म का हिस्सा हैं या नहीं इसको लेकर उन्होंने अब स्थिति साफ कर दी है।

### मैं एकसाथ कई फिल्में नहीं करता

हैदराबाद में अपनी मलयालम फिल्म 'पल्लीचट्टाम्बी' के प्रमोशन के दौरान टोविनो थॉमस ने स्पष्ट किया कि वो प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने बताया कि शेड्यूल में टकराव के कारण उन्होंने 'ड्रैगन' छोड़ दी। एक्टर ने कहा कि डेट्स मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं यह फिल्म नहीं कर रहा हूं। मैं एक साथ कई फिल्में नहीं करता। मलयालम में हम एक ही शेड्यूल में फिल्म पूरी कर लेते हैं। लेकिन तेलुगु में, एक प्रोजेक्ट में लगभग एक साल लग जाता है। मैं तीन महीने दे सकता हूं, पूरा साल नहीं।

### 25 जून को रिलीज होनी है फिल्म

एनटीआर-नील के नाम से मशहूर इस तेलुगु फिल्म को फिलहाल 'ड्रैगन' के नाम से पहचाना जा रहा है। यह तेलुगु सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को 25 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होना है। हालांकि, फिल्म के आगे बढ़ने और टलने की भी खबरें सामने आईं, लेकिन अभी तक मेकर्स की ओर से इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। फिल्म में जूनियर एनटीआर के अलावा रुक्मिणी वसंत और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

### 'वॉर 2' में नजर आए थे जूनियर एनटीआर

जूनियर एनटीआर आखिरी बार ऋतिक रोशन के साथ 'वॉर 2' में नजर आए थे। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है। यह यशराज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। हालांकि, फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

## मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं...

कृतिका कामरा ने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी, वह टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थीं लेकिन अचानक ही सबकुछ छोड़ दिया। टीवी से फिल्मों और वेब सीरीज की तरफ रुख किया। धीरे-धीरे वह यहां भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। हालिया रिलीज सीरीज 'मटका किंग' में वह विजय वर्मा के अपोजिट नजर आईं। साथ ही टीवी प्रेजेंटर गौरव कपूर से की गई उनकी सादगी भरी शादी भी खूब चर्चा में रही। कृतिका कामरा ने अपने शुरुआती करियर, पर्सनल लाइफ को लेकर लंबी बातचीत की है।

### खुश हूं कि कम उम्र में शादी नहीं की

कृतिका कामरा ने 37 साल की उम्र में गौरव कपूर से शादी की है। इतनी देर से शादी करने पर वह कहती हैं, "मैं बहुत खुश हूं कि कम उम्र में शादी नहीं की। कम उम्र में हमारी सोच अलग होती है। खासकर छोटे शहरों में लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। मेरी कई दोस्तों की काफी पहले शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। ऐसे माहौल में करियर को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन मैं खुद को खुशनसीब मानती हूं कि मेरे पैरेंट्स ने मुझ पर कभी किसी तरह का दबाव नहीं डाला। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि शादी कब करोगी? उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे भाई को बराबरी से पाला है।"

### वक्त के साथ प्यार को लेकर नजरिया बदल गया

कृतिका कामरा बताती हैं कि टीनएज में उनकी सोच भी रोमांटिक किस्म की थी। लेकिन वक्त के साथ नजरिया बदल गया। वह कहती हैं, 'टीनएज में हम जो देखते-सुनते हैं, उसी से हमारी सोच बनती है। फिल्में, गाने और आसपास का माहौल एक तरह का रोमांटिक नजरिया बना देते हैं। मैं खुद भी काफी रोमांटिक हूं। एक्टर होने के नाते ये चीजें और गहराई से महसूस करती हूं। लेकिन समय के साथ यह सोच बदलती है। आप अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। अपने और दूसरों के रिश्तों को बनते-बिगड़ते देखते हैं और धीरे-धीरे चीजों को अलग नजरिए से समझने लगते हैं।

### मैं और गौरव दोनों सेल्फ-मेड हैं

अपने लाइफपार्टनर गौरव कपूर के बारे में कृतिका कहती हैं, 'अब मैं अपने आप को ज्यादा फ्री महसूस करती हूं। मैं लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने के लिए फैसले नहीं लेती हूं। मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती हूं। मैं इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। गौरव भी मेरी तरह के इंसान हैं, वो भी सेल्फ मेड हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू किया और अपनी लाइफ खुद बनाई। वो मेरी जर्नी को समझते हैं। हम दोनों अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंट लोग हैं और अब एक हो गए हैं। अभी शादी को एक महीना ही हुआ है लेकिन ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ बदल गया है। मैं जो जिम्मेदारियां पहले निभा रही थीं, वही हम दोनों मिलकर निभा रहे हैं।'

### पीक पर छोड़ा था टीवी का करियर

टीवी सीरियल की दुनिया में कृतिका कामरा ने बहुत जल्द पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी, उनका करियर पीक पर पहुंच गया था। फिर अचानक टीवी छोड़कर फिल्मों में आईं। इस पर कृतिका कहती हैं, 'मेरी जिंदगी का दूसरा रिस्क तब था जब मैंने टीवी छोड़ा। उस वक्त मैं बहुत अच्छी पोजिशन में थी। मैं टेलीविजन में हिट हो चुकी थी। अच्छा पैसा मिल रहा था और अपने तरीके से काम करने की एक जगह बन गई थी। लेकिन उसी पीक पर मैंने वह सब छोड़ दिया। उस वक्त बहुत लोगों ने कहा कि यह बहुत बड़ा रिस्क है। इतना सिक्योर काम और पैसे छोड़ना ठीक नहीं है। लोग कहते थे कि टेलीविजन से बाहर निकलकर आगे बढ़ना आसान नहीं होता। कई लोग वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अब उस बात को भी 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए, मुझे उन सभी के लिए प्यार मिला और मेरी एक फिल्मोग्राफी बनी है, जिसमें वैरायटी है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं।'

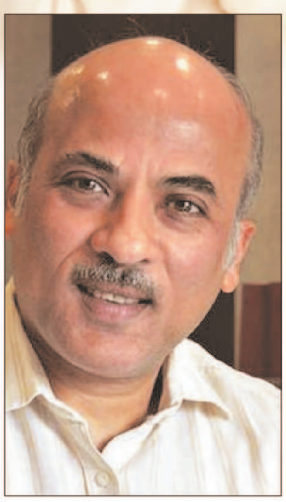

## पहली बार आयुष्मान खुराना संग काम करेंगे सूरज बड़जात्या

'हम साथ साथ हैं', 'हम आपके हैं कौन' और 'विवाह' जैसी हिट फिल्मों के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने अपनी अगली फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। सूरज बड़जात्या ने आखिरी फिल्म 'ऊंचाई' डायरेक्ट की थी। अब इन दिनों वे अपनी अगली फिल्म बनाने में व्यस्त हैं। फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी डायरेक्टर ने कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये अपडेट शेयर किया, और फिल्म से जुड़ी बाकी जानकारी भी दी। सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म का नाम आधिकारिक तौर पर 'ये प्रेम मोल लिया' रखा गया है। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस राजश्री फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की और इसे एक फैमिली एंटरटेनर बताया है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी लीड रोल में नजर आएंगे। अब तक इस प्रोजेक्ट की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन मंगलवार सुबह मेकर्स ने फिल्म का टाइटल और रिलीज डेट दोनों अनाउंस कर दिए। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया तैयार कर रहे हैं। राजश्री फिल्म्स इस फिल्म को महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में फिल्म से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

## मैन वर्सेस मशीन पर आधारित होगी 'तेरी बातों में ऐसा...2' स्क्रिप्ट जल्द होगी लॉक

साल 2024 में आई 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने भारतीय सिनेमा में 'इंसान और मशीन' के रिश्ते पर एक एक्सपेरिमेंट पेश किया था। करीब 133.64 करोड़ के ग्लोबल कलेक्शन के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई। अब खबरें हैं कि इसका सीक्वल यानी 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2' जल्द ही अपने अगले फेज में एंटर करने वाला है।

मैडॉक फिल्म्स ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए राइटिंग टीम को एक्टिव कर दिया है। स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है और मेकर्स अगस्त 2026 तक इसे फाइनल करने का प्लान बना रहे हैं। फिल्म 2027 की पहली छमाही में फ्लोर पर जा सकती है।

### फिल्म के दौरान क्रिएटिव चर्चा भी खूब करते थे शाहिद

शूटिंग के दौरान शाहिद सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि क्रिएटिव चर्चा का अहम हिस्सा भी थे। वे रोबोटिक्स की विश्वसनीयता पर लगातार सुझाव देते रहे। वहीं कृति के लिए 'सिफ्रा' का किरदार चुनौतीपूर्ण रहा, जहां उन्हें मशीन और इंसान के बीच संतुलन बनाना था। सीक्वल में उनके किरदार का फोकस 'मशीन इमोशंस' के डेवलपमेंट पर रहेगा।

### 2027 तीनों स्टार्स के लिए बड़ा, आएंगे कई प्रोजेक्ट

बता दें कि साल 2027 शाहिद, कृति और जाह्नवी के करियर के लिहाज से भी अहम रहने वाला है। जहां शाहिद एक्शन और थ्रिलर जॉनर में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में हैं, वहीं कृति अपने प्रोडक्शन हाउस 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' के तहत नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। दूसरी ओर, जाह्नवी पैन-इंडिया और साउथ प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने करियर को नए स्तर पर ले जाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। दिनेश विजन के लिए भी यह सीक्वल एक सुरक्षित दांव होगा।

### जाह्नवी कपूर की एंट्री से बढ़ेगा फिल्म का स्केल

पहले पार्ट के अंत में जाह्नवी कपूर की एंट्री ने जो सस्पेंस छोड़ा था, वह सीक्वल में बड़ा मोड़ लेने वाला है। इस बार शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ जाह्नवी एक अहम भूमिका में दिखेंगी, जिससे कहानी का स्केल दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

### सीक्वल में दिखेगा टेक्नोलॉजी और भावनाओं का संघर्ष

ट्रेड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीक्वल का मुख्य थीम 'मैन वर्सेस मशीन' का क्लैश होगा। AI और ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बढ़ते प्रभाव के बीच फिल्म इस फिक्शन को हकीकत से जोड़ने की कोशिश करेगी। कोडिंग के जरिए रोबोट्स में जज्बात डालने की कोशिश और उससे पैदा होने वाली गड़बड़ियां कहानी में नया रोमांच जोड़ेंगी।

## नाम के साथ पैसा कमा रहीं ये अभिनेत्रियां! फिल्मों के अलावा इन कारोबार में है दबदबा

बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से फिल्मी दुनिया में नाम कमाया है। कई ऐसी अभिनेत्रियां भी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के अलावा दूसरी इंडस्ट्रियों में काम करके अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। इनमें से कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं, जिन्होंने एक्टिंग के अलावा कारोबार में भी हाथ आजमाया है और कामयाबी हासिल की है।

### आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने साल 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है। उन्होंने बच्चों के कपड़ों के एक ब्रांड की स्थापना की है। आलिया की इस पहल को समझदारी भरा निवेश माना जाता है।

### दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने 2006 में कन्नड़ फिल्म 'ऐश्वर्या' से एक्टिंग में डेब्यू किया। उन्होंने 2007 में 'ओम शांति ओम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने एक ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया है। इस ब्रांड की भारत ही नहीं दुनियाभर में चर्चा है।

### प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने तमिल फिल्म 'थमिजान' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। उन्होंने हॉलीवुड तक का सफर तय किया है। वह एक हेयर केयर ब्रांड की मालकिन हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क में एक भारतीय रेस्टोरेंट भी खोला है। इससे पता चलता है कि अभिनेत्री एक कामयाब कारोबारी भी हैं।

### सोनम कपूर

साल 2007 में फिल्म 'सांवरिया' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री सोनम कपूर भी एक कारोबारी हैं। उन्होंने अपनी बहन रिया के साथ मिलकर कपड़ों का एक ब्रांड बनाया है। अभिनेत्री को फिल्मों में काम करने के अलावा दूसरी चीजों का भी शौक है।

### अनुष्का शर्मा

साल 2008 में अनुष्का शर्मा ने फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' से फिल्मों में डेब्यू किया। फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। वह एक सफल कारोबारी भी हैं। वह एक प्रोडक्शन हाउस की सह-स्थापना हैं। इस प्रोडक्शन हाउस के तहत कई मशहूर सीरीज बनी हैं। भारत में वह एक सफल निर्माता के तौर पर उभरी हैं।

# एक मई से सुशासन तिहार 2026 होगा प्रारंभ, आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

## जनसमस्या निवारण शिविर में आमजनो के मांगो व शिकायतों का समयबद्ध और और प्रभावी निराकरण करें सुनिश्चित

*नई दृष्टिबिंदु / मोहला*

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने आगामी सुशासन तिहार 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर डीआर ध्रुव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी कमर्चारी उपस्थित रहें।

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कहा कि जिले में 1 मई से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्लस्टरवार जनसमस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों के लिए स्थान चिन्हांकन, आवश्यक व्यवस्थाएं और विस्तृत काययीजना समय से तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कमर्चारी इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें, ताकि इसका सफल क्रियान्वयन हो सके।

बैठक में कलेक्टर ने जनदर्शन एवं मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने मानपुर स्थित नवनिर्मित एकलव्य आवासीय विद्यालय में नए शिक्षा सत्र के लिए विद्याथिर्यो की शिफ्टिंग को लेकर विशेष निर्देश दिए। साथ ही विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, सिकल सेल एनीमिया, कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा आयरन टेबलेट वितरण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाएं।

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में अनुशासन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने विभाग में रिक्त पदों की स्थिति, महतारी वंदन योजना, ई-केवाईसी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, आभा आईडी एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति की जानकारी ली। साथ ही विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की भी विस्तृत समीक्षा की।

**खास खबर**

# कलेक्टर यादव ने जनदर्शन में गंभीरता से सुनी नागरिकों की समस्याएं

*नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव*

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनमानस उम्मीद लेकर जनदर्शन में आते है। उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए समाधान शीघ्र करें। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, भू-अर्जन, अवैध अतिक्रमण हटाने, सीमांकन, नजूल से संबंधित, पेंशन, राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने जैसे आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

## जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता

**बेमेतरा।** जिला बेमेतरा में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है। जिले में संचालित सभी 75 पेट्रोल एवं डीजल पंपों पर नियमित रूप से ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। इसी प्रकार, जिले में कार्यरत 16 गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को निरंतर एलपीजी गैस उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन द्वारा पूर्व में ही गैस बुकिंग के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित गैप दिवस तय किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक तरीके से गैस मिल सके।

हाल ही में पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर कुछ माध्यमों में भ्रामक एवं अपुष्ट खबरें प्रसारित हो रही हैं, जिनका जिले की आपूर्ति व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। इन अफवाहों के कारण आमजन में अनावश्यक भ्रम की स्थिति बन रही है और लोग पेट्रोल पंपों एवं गैस एजेंसियों पर भीड़ एकत्र कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बनाए रखें तथा आवश्यकतानुसार ही ईंधन एवं गैस का उपयोग करें। प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक सेवाओं की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और आपूर्ति व्यवस्था निरंतर बनी रहे।

जिले में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार क्डउछ से संबंधित एजेंसियों में 872 घरेलू सिलेंडर, 43 व्यावसायिक सिलेंडर तथा 92 नग 5 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर उपलब्ध हैं। वहीं ल्ढउछ एजेंसियों में 153 घरेलू सिलेंडर, 5 व्यावसायिक सिलेंडर एवं 15 नग 5 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर जिले में 1025 घरेलू सिलेंडर, 48 व्यावसायिक सिलेंडर तथा 107 नग 5 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। विभिन्न ब्लॉकों में बालसमुंद (बेमेतरा) में सर्वाधिक 324 घरेलू सिलेंडर, नांदघाट (नवागढ़) में 245 तथा सीबीसिस (नवागढ़) में 115 सिलेंडर उपलब्ध हैं, जबकि कुछ एजेंसियों में स्टॉक शून्य भी दर्ज किया गया है जिला प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन एवं गैस की कोई कमी नहीं है। नागरिकों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सामान्य रूप से सेवाओं का उपयोग करें।

# सुशासन तिहार से पहले लंबित प्रकरणों के निराकरण करें - कलेक्टर जितेन्द्र यादव

## कार्य पर लापरवाही करने पर राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने के दिए निर्देश

*नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव*

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने 1 मई से प्रारंभ होने वाले प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के पूर्व अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की मैदानी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कहा कि सुशासन तिहार के पहले अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, लंबित मनरेगा मजदूरी भुगतान, हैण्डपंप सुधार, विद्युत व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान क्लस्टर बनाकर जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में कार्य में लापरवाही बरतने पर राजनांदगांव विकासखंड के राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करने तथा अधिकारी-कर्मचारियों को आईगोट कमयीगी पोर्टल में ऑनबोर्डिंग कर निर्धारित कोर्स पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना पोर्टल पर मोबाइल के माध्यम से अपना फार्म भरकर डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण की। कलेक्टर ने राजस्व विभाग को शासकीय योजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग द्वारा पिछले एक सप्ताह में अविवादित नामांतरण, खात विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन जैसे राजस्व प्रकरण कुल 498 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। कलेक्टर ने किशोरी बालिकाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव हेतु एचपीवी टीकाकरण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा अधिकाधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में 852 बालिकाओं का वैक्सीनेशन हो गया है, जो प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने जिला चिकित्सालय में रसोई घर शिफ्टिंग कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने तथा परिसर में किराया बकाया रखने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सीलिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले एक सप्ताह में 1 लाख रूपए किराया राशि जमा की गई है। जिले के राजगामी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। जिले में अब तक 2 हजार 311 घरों में सोलर पैनल लग चुका है।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन की जानकारी ली। जिले में 5 हजार 618 कनेक्शन प्रदाय के लक्ष्य के विरूद्ध 8 हजार 110 पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर 7 हजार 119 हितग्राहियों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड ई-केवाईसी हेतु शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससे हितग्राहियों को समय पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन उपलब्ध हो सके। कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य प्रतिष्ठानों में नियमित जांच कर अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीदी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पंजीकृत सभी किसानों की उपज का शत-प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रेडा विभाग द्वारा स्थापित खराब सिंचाई पंपों की जांच कर शीघ्र सुधार करने तथा ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जिले के 3 हजार 357 हैण्डपंपों का सुधार कार्य किया जा चुका है। बैठक में सियान गुड़ी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं जनदर्शन के प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

# खनिजों का अवैध परिवहन व उत्खनन करने पर लगातार की जा रही कार्रवाई

## अवैध परिवहन एवं उत्खनन करने पर 3 वाहन और एक जेसीबी किया जप्त

*नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव*

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनि अधिकारी ने बताया कि खनिज विभाग की टीम द्वारा राजनांदगांव तहसील अंतर्गत ग्राम कुंवारझोलकी, ठेलकाडीह, ढारा, मोहारा, डोंगरगढ़, बोरतलाव, सुकुलदैहान, घुमका सहित विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की गई। जिसमें अहिवारा निवासी अरूण गुप्ता के स्वामित्व की हाईवा 12 चक्का सीजी 04 एमजे 6242 से पिठौरा निवासी वाहन चालक अनिल कुमार द्वारा चूना पत्थर (गिट्टी) तथा दुर्ग निवासी सेवासिंह ओबेरॉय के स्वामित्व के हाईवा सीजी 07 बीजे 9929 से चंवरढाल निवासी वाहन चालक विक्की साहू द्वारा मुरूम व मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए थाना ठेलकाडीह को सुपुर्द किया गया।

इसी तरह ढारा निवासी राजेन्द्र जंघेल के स्वामित्व की माजदा सीजी 08 एल 3688 से कातुलवही निवासी वाहन चालक गन्नू विश्वकर्मा द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने तथा ढारा निवासी राजेन्द्र जंघेल के स्वामित्व के जेसीबी सीजी 07 एनए 8565 से ढारा निवासी वाहन चालक अज्जू यादव द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन करने पर कार्रवाई करते हुए थाना मोहारा को सुपुर्द किया गया। प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए लगातार गस्त व निगरानी की जा रही है।

# निर्धारित दर से अधिक मदिरा विक्रय करने पर सेल्समैन को कार्य से किया अलग

*नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव*



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर मदिरा विक्रय करने के मामले की जांच की गई। वायरल वीडियो के आधार पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त प्रभारी राजनांदगांव दक्षिण द्वारा जांच उपरांत संबंधित सेल्समैन को कार्य से पृथक कर दिया गया है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए रेवाड़ीह-01 स्थित विदेशी (कंपोजिट) मदिरा दुकान का दौरा कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि वीडियो में दिखाए गए ब्रांड वन शॉट व्हिस्की की पाव 150 रूपए के स्थान पर 200 रूपए में, यानी 50 रूपए अधिक दर पर सेल्समैन युगल किशोर खरे द्वारा विक्रय की गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित सेल्समैन को कार्य से पृथक कर ब्लैकलिस्ट करने हेतु उच्च विभाग को पत्र भेजा गया। जिले में किसी भी मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय की सूचना आबकारी उप निरीक्षक मुकेश वर्मा के मोबाईल नंबर 8412900180 पर दी जा सकती है।

# मिट्टी परिवहन के लिए शर्तों व निर्देशों का पालन नहीं करने पर अनुमति निरस्त

*नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव*



कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव द्वारा मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत खुर्सीपार स्थित बिल्हरी जलाशय के गहरीकरण कर मलबा, मिट्टी परिवहन हेतु शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 01 राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को दिये गये निर्देशों का अव्हेलना कर गहरीकरण किया जा रहा है, जिससे जलाशय को भविष्य में क्षति पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा डुबान क्षेत्र में बांधपार से 60 मीटर दूरी छोड़कर गहरीकरण किया जाना था, किन्तु कंपनी द्वारा निर्देशों का अनदेखा कर बांधपार से 25-30 मीटर दूरी छोड़कर गहरीकरण किया जा रहा है। कंपनी को 0.60 मीटर गहरीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी, किन्तु कंपनी द्वारा 2 से 2.50 मीटर गहराई कर गहरीकरण किया जा रहा है। कंपनी को दिये गये निर्देश में बांधपार के डाऊन स्ट्रीम में 200 पौधे (ट्री गार्ड के साथ) लगाया जाना था, किन्तु कंपनी द्वारा नहीं लगाया गया है। कंपनी द्वारा जलाशय के स्थाई संरचना को लगातार नुकसान पहुंचाया गया है।

मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को शर्तों का पालन नहीं करने के कारण अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बांध एवं बांध के भीतर किये गये क्षति को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर सिंचाई अधिनियम के तहत कंपनी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

# जिला स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा : कलेक्टर ने गुणवत्ता, समयबद्धता और मॉनिटरिंग पर दिया जोर

*नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़*



जिला कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध और प्रभावी रूप से पहुंचे तथा सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

कलेक्टर ने एएनसी जांच, संस्थागत प्रसव सेवाओं और शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत पूर्ण टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही छूटे हुए बच्चों की पहचान कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी), चिरायु योजना और एनीमिया मुक्त भारत अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने कहा कि कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। बैठक में क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन, मलेरिया नियंत्रण, सिकल सेल नियंत्रण, अंधत्व निवारण, एनसीडी कार्यक्रम, टेली कंसल्टेशन सेवाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए। स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी होनी चाहिए, गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन किया जाए और कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिए गति बढ़ाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं सीधे आमजन के जीवन से जुड़ी होती हैं, इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत, सिविल सर्जन डॉ. दिनेश पटेल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैकरा सहित स्वास्थ्य समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

# जिले में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 26 को 24 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

*नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव*

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 26 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का राज्यव्यापी आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 99 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 24 हजार 185 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से 12.15 बजे तक रहेगा। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

व्यापम द्वारा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यथियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए है। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश सुबह 9.30 बजे के बाद पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। अभ्यथियों को परीक्षा केंद्र में कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचे ताकि फ्रिस्किंग, पहचान सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूर्ण हो सकें। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ मान्य फोटो पहचान पत्र लाना होगा। अभ्यर्थी हल्के रंग के सादे कपड़े पहनकर आएं। गहरे रंग, भारी डिजाइन, फैंसी या संदिग्ध कपड़ों से बचें। जूते की जगह चप्पल व सैंडल पहनने। परीक्षा केंद्र में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ व स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी लिखित सामग्री, नोट्स या पुस्तिका, धातु व इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, वस्तुएं किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल व पयर्वेक्षण की व्यवस्था की गई है। फ्रिस्किंग की कड़ी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा अभ्यथियों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचें, नियमों का पालन और शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से परीक्षा में सम्मिलित होने की अपील की गई है।

# विधायक रिकेश को बड़ी जिम्मेदारी : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति में हुए शामिल

*नई दृष्टिबिंदु / भिलाई*

भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रिकेश सेन के नाम एक और बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि जुड़ी है। भारत सरकार ने उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया है।

### विधायक रिकेश सेन की भूमिका

भारत सरकार के संयुक्त सचिव समर नंदा ने आधिकारिक पत्र भेजकर विधायक रिकेश सेन को इस नियुक्ति की बधाई दी है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि समिति की बैठकों में उनकी सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में अमूल्य साबित होगा।

### क्षेत्र में खुशी की लहर

विधायक रिकेश सेन को मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र वैशाली नगर और पूरे भिलाई में हर्ष का माहौल है। समर्थकों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में जगह मिलना न केवल विधायक सेन के कद को बढ़ाता है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है।

### पीएम करेंगे समिति की अध्यक्षता

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इस विशेष समिति की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस समिति में देश की चुनिंदा 126 हस्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें विधायक रिकेश सेन को 91वें क्रम पर सदस्य के रूप में स्थान मिला है।

### दो साल तक चलेगा राष्ट्रव्यापी उत्सव

महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक दो वर्षों तक पूरे देश में मनाया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य ज्योतिबा फुले के सामाजिक न्याय, समानता और महिला सशक्तिकरण के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 126 सदस्यीय टीम राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर भी मार्गदर्शन देगी। इस समिति का गठन 13 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर गजट में प्रकाशित किया जा चुका है।

## पावर हाउस चौक भिलाई पर अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी निगम की कार्रवाई

*नई दृष्टिबिंदु / भिलाई*

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने एवं सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने के उद्देश्य से पावर हाउस चौक पर दूसरे दिन भी सख्त कार्रवाई की गई।

निगम की टीम ने उन व्यापारियों एवं ठेला संचालकों पर कार्रवाई की, जो सड़क के बीचों-बीच सामान रखकर या फल-ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे थे। ऐसे अतिक्रमण के कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। कार्रवाई के दौरान निगम अमले ने सड़क पर रखे सामान को हटवाया तथा संबंधित लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि वे निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय करें। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में पुनः अतिक्रमण पाए जाने पर जुर्माना एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम अधिकारियों ने बताया कि पावर हाउस चौक शहर का अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में सड़क पर अतिक्रमण से आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। नगर निगम ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और सड़क पर अतिक्रमण न करें, ताकि शहर को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाया जा सके।

### महापौर यादव ने 15 लाख के लाभ का बजट पेश किया

**राजनांदगांव।** नगर पालिक निगम की बजट बैठक 22 अप्रैल अपराह्न 12 बजे नगर निगम टाउन हाल सभागृह में प्रारंभ हुई, बैठक में पुनरीक्षित आय-व्यय वर्ष 2025-26 एवं प्रस्तावित आय-व्यय बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृति के संबंध में विचार-विमर्श उपरांत निर्णय लिया जाना था। बजट बैठक निर्धारित समय में राष्ट्रगीत तथा राज्य गीत के साथ प्रारंभ हुई। बैठक के प्रारंभ में महापौर मधुसूदन यादव ने अपना द्वितीय बजट प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदन का पठन किया, उन्होंने 15 लाख के लाभ का बजट पेश कियाजिसके पश्चात पाषर्दों ने चर्चा में भाग लिया, चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय का बजट सर्व सम्मति से पारित किया गया। बैठक के अंत में राष्ट्रगान के पश्चात निगम के दिवंगत कर्मचारी किशन सिंह राजपूत एवं पहलगाम में हुए आतंकी हमला में मृतको को दो मिनट की मौन श्रद्धांजली दी गयी।

## नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाली 'महिला विरोधी' कांग्रेस का भाजयुमो ने फूंका पुतला

### महिलाओं के हक की राह में रोड़ा बनी कांग्रेस : सौरभ जायसवाल

*नई दृष्टिबिंदु / भिलाई*

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान एवं भाजपा भिलाई जिला संगठन के मार्गदर्शन में आज भिलाई की सड़कों पर कांग्रेस के विरुद्ध भारी आक्रोश देखने को मिला। भाजयुमो भिलाई जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' की राह में रोड़ा अटकाने और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ छल करने के विरोध में आयोजित किया गया।

भाजयुमो जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनकी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पुरानी परंपरा को दोहराते हुए महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है।

"कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश में मातृशक्ति का नेतृत्व बढ़े। वह महिलाओं को केवल एक 'वोट बैंक' की तरह इस्तेमाल करती आई है। इस अधिनियम का विरोध करके कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि वह बुनियादी रूप से एक महिला विरोधी पार्टी है।"

### विपक्ष का असली चरित्र उजागर

भाजयुमो ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सदन के भीतर और बाहर इस बिल का विरोध कर देश की करोड़ों महिलाओं की प्रगति को रोकने का प्रयास किया है। विपक्षी गठबंधन का यह कृत्य उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

### भिलाई की सड़कों पर उतर कर युवा मोर्चा ने जन-आक्रोश किया

देशभर की महिलाओं में जहाँ इस बिल को लेकर भारी उत्साह और खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति ने मातृशक्ति को अपमानित किया है। इसी अपमान का बदला लेने और जनता को कांग्रेस के असली चेहरे से अवगत कराने के लिए भाजयुमो भिलाई ने उग्र प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजयुमो भिलाई जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल जिला महामंत्री अमित राजपूत भाजयुमो में जिला उपाध्यक्ष शुभम चिंचोलकर, सौरभ चटर्जी, तुषार देवांगन प्रवीण यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष स्वाटी कौशिक जी जिला मंत्री अपर्णा मुखर्जी,नितेश सिंह अखिलेश सिंह,सिद्धार्थ रावत, कन्या शक्ति माही तिवारी समीक्षा दीपशिखा जिला कार्यालय प्रभारी नरेंद्र वर्मा मंडल अध्यक्ष मनीष चौधरी,चंदन यादव, अनुराग मार्कंडेय,संदीप पाली,भास्कर राव,मनीष, भोला कुंभकार राजेश यादव,जिला कार्यालय मंत्री बसन्त राजपूत मंडल महामंत्री अर्पित तिवारी राज मिश्र,सतबीर सिंह,नीतीश राय एवं युवा मोर्चा के जिला एवं बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त जानकारी युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी जयंत शर्मा ने दी।

## अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का पर्दाफाश, 43.120 किलो गांजा के साथ दो आरोपी हुए गिरफ्तार

*नई दृष्टिबिंदु / महासमुंद*

पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में संलिप्त दो अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 43.120 किलोग्राम गांजा सहित लगभग 24 लाख 76 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति जप्त की गई है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से एक कार के माध्यम से गांजा की खेप महासमुंद होते हुए महाराष्ट्र ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर एक संदिग्ध सफेद होंडा सिटी कार को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर कार के विभिन्न हिस्सों—बैक लाइट के खोल, अलग से बनाए गए चैंबर, डिक्की एवं सीट के पीछे—में छिपाकर रखे गए कुल 43.120 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम श्यामल बसंत वासनिक (33 वर्ष) एवं दानिस अंसारी (30 वर्ष), दोनों निवासी नागपुर (महाराष्ट्र) बताया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे उक्त गांजा उड़ीसा के फुलवानी क्षेत्र से लाकर नागपुर में खपाने की तैयारी में थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा, प्रयुक्त वाहन तथा दो मोबाइल फोन जप्त किए हैं। मामले में थाना महासमुंद में अपराध क्रमांक 216/2026 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, पिछले तीन महीनों में जिले में गांजा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए 77 प्रकरणों में 5748.508 किलोग्राम गांजा जब्त किया जा चुका है तथा 197 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बड़ी संख्या अन्य राज्यों के आरोपियों की है। महासमुंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

## सेक्टर 4 श्री जगन्नाथ मंदिर में "बाबा भज विश्वनाथ" का 11वां स्थापना दिवस मनाया

*नई दृष्टिबिंदु / भिलाई*

### भजन संध्या और भव्य महाआरती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, मंदिर शिल्पी और कलाकारों का हुआ सम्मान

सेक्टर 4 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थापित "बाबा भज विश्वनाथ" महादेव मंदिर का 11 वां स्थापना दिवस 22 अप्रैल 2026 को अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। तिथि अनुसार आयोजित इस एक दिवसीय उत्सव में सुबह से लेकर देर रात तक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महादेव के दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के साथ हुआ, जो दोपहर 2 बजे तक चला। कार्यक्रम के मुख्य जजमान बसंत प्रधान ने सपरिवार विधि-विधान से अभिषेक संपन्न किया। संध्या 7 बजे मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा, जब ढोल, नगाड़े और घंटवाद्य के साथ भव्य महाआरती की गई। इस अवसर पर हुई आकर्षक आतिशबाजी ने उत्सव की भव्यता में चार चांद लगा दिए।

देर रात तक चली भजन संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र (इरड) के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी) विजय कुमार बेहेरा उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सेफी चेयरमैन एवं बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष व समाजसेवी संजय मिश्रा, जगन्नाथ समिति के महासचिव सत्यवान नायक एवं कार्यक्रम के जजमान बसंत प्रधान मंचस्थ रहे।

### शिल्पियों और कलाकारों का किया गया सम्मान

समिति द्वारा इस अवसर पर मंदिर के शिल्पी आनंद महाराणा तथा महाआरती में उत्कृष्ट ढोल वादन करने वाले कलाकार शत्रुघ्न स्वांई को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही भजन संध्या में अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से भक्तों को मंत्रमुग्ध करने वाले कलाकारों—मधुस्मिता दीक्षित, अंकित साहू, निकिता साहू, श्रेया नाहक, सविता देवांगन, दिलीप साहू, विश्व बंधन नाथ, राहुल किशन, गोविंद, अनिल, प्रकाश देवांगन और चितरंजन दास को भी सम्मानित किया गया।

श्री जगन्नाथ समिति के महासचिव सत्यवान नायक ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता में बसंत प्रधान, त्रिनाथ साहू, कवि बिस्वाल, अनाम नाहक, रवि स्वाई, वृंदावन स्वाई, बीसी बिस्वाल, प्रकाश स्वाई,सुशांत सतपति, रंजन महापात्र, निरंजन महाराणा, प्रकाश दास, वीके होता, सुभाष पात्रो, हिमांशु शांति,परितोष पाणिग्रही, आकाश व अविनाश प्रधान, श्रीमती कर्दबिनी प्रधान एवं श्रीमती सुजाता साहू सहित उत्कल समाज के वरिष्ठ जनों का विशेष योगदान रहा। महाप्रसाद सेवन के साथ इस भव्य आयोजन का समापन हुआ। समिति ने सभी भक्तजनों की उपस्थिति और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100